



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237852
CG-DL-E-02082022-237852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]
No. 191]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

मामला सं. एडी-ओआई-11/2021

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8 के रूप में भी जाना जाता है” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06/11/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “एडी नियमावली” भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक अथवा “याचिकाकर्ता” कहा गया है) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण

हेतू) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से “(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8 के रूप में भी जाना जाता है (उसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की मांग करते हुए एक आवेदन/याचिका दायर की है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/11/2021-डीजीटीआर दिनांक 2 अगस्त, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 अगस्त, 2021 को सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने दिनांक 2 अगस्त, 2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन में उपलब्ध कराए गए पत्तों के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने के लिए कहा गया था।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पत्तों के साथ भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने एडी निमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
 - (i) चांगझोऊ यूनाइटेड केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ii) चाइना सिनोफार्म इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड
 - (iii) हांगझोऊ प्रोसेरे केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iv) हार्ड होप इंटरनेशनल ग्रुप
 - (v) जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (vi) झेजियांग मेडिसंस एंड हैल्थ प्रोडक्ट्स
 - (vii) झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड

- छ. इसके उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया:
- (i) झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ii) झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iii) हांगझोऊ प्रोसेरे केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iv) जियांगसु युतियान फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (v) जियांगसु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (vi) जियांगसु पीफ्रि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- ज. निर्यातकों के अलावा, चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमएचपीआईई) ने भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी:
- i. अमोली आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. अरोबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - iii. बाइकूल लिमिटेड
 - iv. डा. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड
 - v. हेटेरो लैब्स लिमिटेड
 - vi. इंड-स्विफ्ट लैबोरेट्रीज लिमिटेड
 - vii. लुपिन लिमिटेड
 - viii. मैकलियोड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 - ix. ऐनालटेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 - x. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xi. काडिला हेल्थकेयर लिमिटेड
- ञ. इसके उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड ने अंतिम स्तर पर आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- i. अमोली आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. डा. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड
- ट. ऊपर प्रस्तुत समस्त अनुरोधों पर उनके संगत होने और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार विचार और समाधान किया गया है।
- ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत/दिए गए साक्ष्य का अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए इस निदेश के साथ उपलब्ध रखा कि पक्षकार डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी संगत पक्षकारों को संबद्ध जांच के लिए संगत हितबद्ध पक्षकारों की सूची के आधार पर ई-मेल से ऐसे अनुरोधों का आदान-प्रदान करेंगे।
- ड. विगत तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना तथा सौदों की आवश्यक जांच के बाद अपने विश्लेषण के लिए आयात आंकड़ों के डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार ब्यौरों पर भरोसा किया है।

- ड. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और भारत में संबद्ध वस्तु के निर्माण व बिक्री की लागत और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 माह) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 – अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 और जांच की अवधि पर विचार किया गया है।
- त. आवेदक, संबद्ध देश से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक डेस्क सत्यापन किया गया था। आवश्यक संशोधन/सुधार, यथा लागू, के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 28 अक्तूबर, 2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को 8 नवंबर, 2021 तक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने और 15 नवंबर, 2021 तक खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- द. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अब तक किए गए अनुरोधों पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच के संगत होने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित ढंग से विचार और समाधान किया गया।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय रूपांतर का पर्याप्त सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- न. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है, अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार विचार/अवलोकन दर्ज किए हैं।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम में ***गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डालर=75.22 भारतीय रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु निम्नलिखित रूप में परिभाषित की गई थी:-

विचाराधीन उत्पाद

3.विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "(4आर-सीआईएस)-1, 1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1, 3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8" है। यद्यपि उत्पाद का रासायनिक नाम "(4आर-सीआईएस)-1, 1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1, 3-डायोक्सेन-4-एसिटेट" है, तथापि इस उत्पाद को एटीएस-8, एएससी-3पी, टीबीआईएन, साइनो कैटल कम्पाउंड और एटोरवेस्टेटिन इंटरमीडिएट एटोरवेस्टेटिन जैसे व्यापारिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें एटीएस-8 सर्वाधिक प्रचलित व्यापारिक नाम है।

4. एटीएस-8 एटोरवेस्टेटिन एपीआई (सक्रिय भेषज अवयव) के विनिर्माण के लिए प्रमुख मध्यवर्ती वस्तु है। एटोरवेस्टेटिन नुस्खे का व्यापक रूप से मनुष्यों में कोलस्ट्रॉल अधिक होने की स्थिति का ईलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे अन्यथा ईलाज न होने पर कार्डिया वेस्कुलर समस्याएं जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। यह एक जीवन रक्षक औषधि है जो अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची(एनएलईएम) के अंतर्गत वर्गीकृत है। मध्यवर्ती वस्तु को कंपनी द्वारा बल्क पाउडर रूप में बनाया जाता है और इसकी कोई अलग ग्रेड और प्रकार नहीं हैं।

5. पीयूसी के आयातों की सूचना आयातों के समय शुल्क लगाने के प्रयोनार्थ अध्याय 29 के उप शीर्षों के अंतर्गत दी गई है जिनमें सर्वाधिक आयात उप शीर्ष संख्या 2932 और 2933 के अंतर्गत हुए हैं यद्यपि याचिका के अनुसार 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 और 2934 जैसे अन्य उप शीर्षों के अंतर्गत भी आयात हुए हैं।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं की निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक और संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु मानते हैं।”

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- विचाराधीन उत्पाद (“पीयूसी”) “(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8” है। यद्यपि उत्पाद का रासायनिक नाम “(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट” है, तथापि इस उत्पाद को एटीएस-8, एएससी-3पी, टीबीआईएन, साइनो कैटल कम्पाउंड और एटोरवेस्टेटिन इंटरमीडिएट एटोरवेस्टेटिन जैसे व्यापारिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें एटीएस-8 सर्वाधिक प्रचलित व्यापारिक नाम है।
- एटीएस-8 एटोरवेस्टेटिन एपीआई (सक्रिय भेषज अवयव) के विनिर्माण के लिए प्रमुख मध्यवर्ती वस्तु है। जांच में शामिल संबद्ध वस्तु पीओआई सहित इस अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई है और ऐसी वस्तुएं इसी अवधि में चीन जन.गण. से भारत में आयात की जा रही हैं।
- प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के “समान वस्तु” मान सकते हैं।
- एक प्रयोक्ता/आयातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीयूसी के कुछ आयात याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में शुद्धता संबंधी समस्याओं के कारण हो रहे हैं। यह दलील निराधार है, वास्तव में यह मुद्दा केवल मौखिक रूप से उठाया गया किंतु लिखित में पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है और निर्यातकों द्वारा दिए गए ऐसे सभी शुद्धता स्तरों की आपूर्ति याचिकाकर्ता द्वारा भी की जाती है। याचिकाकर्ता के पास शुद्धता के उच्चतम संभव स्तर के रसायन को प्राप्त करने की तकनीकी क्षमता है। किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने शुद्धता या अन्य पहलुओं की दृष्टि से उत्पाद में अंतर का कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जांच में शामिल उत्पाद प्रतिवादी द्वारा उत्पादित और बेचा गया (4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8 है।
- ii. भारत को निर्यातित पीयूसी और घरेलू बाजार में या अन्य देशों को निर्यातित पीयूसी के बीच भौतिक/तकनीकी/रासायनिक विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है।
- iii. प्रतिवादी द्वारा उत्पादित उत्पाद और प्राधिकारी द्वारा परिभाषित उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट जिसे एटीएस-8" है। यद्यपि उत्पाद का रासायनिक नाम "(4आर-सीआईएस)-1,1-डिमिथाइलेथाइल-6-साइनोमिथाइल-2-2-डिमिथाइल-1,3-डायोक्सेन-4-एसिटेट" है, तथापि इस उत्पाद को एटीएस-8, एएससी-3पी, टीबीआईएन, साइनो कैटल कम्पाउंड और एटोरवेस्टेटिन इंटरमीडिएट एटोरवेस्टेटिन जैसे व्यापारिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें एटीएस-8 सर्वाधिक प्रचलित व्यापारिक नाम है।
8. एटीएस-8 एटोरवेस्टेटिन एपीआई (सक्रिय भेषज अवयव) के विनिर्माण के लिए प्रमुख मध्यवर्ती वस्तु है। एटोरवेस्टेटिन नुस्खे का व्यापक रूप से मनुष्यों में कोलस्ट्रॉल अधिक होने की स्थिति का ईलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे अन्यथा ईलाज न होने पर कार्डिया वेस्कुलर समस्याएं जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है।
9. पीयूसी के आयातों की सूचना आयातों के समय शुल्क लगाने के प्रयोनार्थ अध्याय 29 के उप शीर्षों के अंतर्गत दी गई है जिनमें सर्वाधिक आयात उप शीर्ष संख्या 2932 और 2933 के अंतर्गत हुए हैं यद्यपि याचिका के अनुसार 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 और 2934 जैसे अन्य उप शीर्षों के अंतर्गत भी आयात हुए हैं।
10. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं"

11. यह नोट किया गया है कि पीयूसी और समान वस्तु के संबंध में प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा कोई तर्क नहीं दिए गए हैं।
12. रिकॉर्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - i. मैसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।
 - ii. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और याचिकाकर्ता संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी आयातक/को या निर्यातक/को से भी संबंधित नहीं है।
 - iii. याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अंतर्गत संबद्ध वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग माने जाने के लिए मापदंडों को पूरा करता है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की योग्यता और उनकी स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे पर कोई पत्र नहीं उठाया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘‘घरेलू उद्योग’’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’’

16. यह नोट किया गया है कि यह आवेदन मै. आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और आवेदक के इस दावे पर किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार ने कोई विवाद नहीं किया है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथा-निर्धारित घरेलू उद्योग के मापदंडों और स्थिति को पूरा करते हैं। प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता/आवेदक को घरेलू उद्योग मानते हैं और आवेदन नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता संबंधी मुद्दे**ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

17. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता संबंधी मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा उनके उत्तर में अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता के कारण घरेलू उद्योग ऐसे प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों/उत्तरों का कोई कारगर खंडन करने में अक्षम बन गया है।
- डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज द्वारा प्रस्तुत आईक्यूआर में मात्रा और कीमत मापदंडों से संबंधित उनके परिशिष्टों में कोई सूचीकरण नहीं दिया गया है और मात्रा तथा औसत कीमत सूचना जैसे संभव स्थानों पर भी सूचीकरण प्रदान नहीं करना गोपनीय को शासित करने वाले पाटनरोधी नियमों का स्पष्ट और घोर उल्लंघन है।
- प्रतिवादी निर्यातकों ने निर्यात मूल्य श्रृंखला में शामिल पक्षकारों के नाम का प्रकटन नहीं किया है और ऐसे ब्यौरे वाले अनुबंधों को गोपनीय माना है। ऐसी मूल सूचना के गोपनीय होने का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी तरह निर्यात मूल्य श्रृंखला में पक्षकारों के नाम किसी दृष्टि से भी गोपनीय नहीं हो सकते हैं और निर्यात मूल्य श्रृंखला में शामिल पक्षकारों के नाम के गोपनीय होने का दावा करना गोपनीयता के नियमों का घोर दुरुपयोग है।
- निर्यातकों ने अपने उत्तर में प्रतिवर्ती सूचीकरण अपनाया है जो प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है। आंकड़ों का ऐसा प्रस्तुतिकरण प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित अपेक्षाओं का उल्लंघन है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा यथा-विहित सूचना प्रस्तुत की है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीय के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- याचिकाकर्ता ने अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया का व्यापक विवरण नहीं दिया है, इसे अस्पष्ट और झूठे कारण बताकर गोपनीय रखा गया है। इन मापदंडों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की एडी नियमावली के नियम 7 के अनुसार अनदेखी की जानी चाहिए।

- ii. याचिकाकर्ता ने उन सौदावार आयात आंकड़ों का साफ्ट प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिन पर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए भरोसा किया है। तथापि, एगजोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2018 की पाटनरोधी अपील सं. 52233 और 52239 में अंतिम आदेश संख्या 50689-50690/2020 दिनांक 12.6.2020] में माननीय सेस्टेट के निर्णय के अनुसार इस आंकड़े को सभी हितबद्ध पक्षकारों से साझा करना आवश्यक है।
- iii. याचिका का अगोपनी रूपान्तरण उसमें लगाए गए आरोपों की तर्कसंगत समझ नहीं दे पा रहा है। याचिकाकर्ता का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का साफ तौर पर उल्लंघन करता है।
- iv. याचिका का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर, 2013 में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल है। याचिका का भाग VI लागत निर्धारण सूचना एनसीवी का हिस्सा नहीं है।
- v. व्यापार सूचना 01/2013 दिनांक 9 दिसंबर, 2013 में याचिकाकर्ता के लिए वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र प्रस्तुत करना अधिदेशित है और ये प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। क्योंकि कुछ शुल्क के भुगतान पर वार्षिक लेख और तुलन-पत्र एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध हैं, इसलिए व्यापार सूचना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

20. नियम 6(7) के अंतर्गत यथाअपेक्षित प्राधिकारी ने एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को जांच में भाग लेने वाले दूसरे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था। यह सूचना भागीदार हितबद्ध पक्षकारों के बीच इस निर्देश के साथ परिचालित की गई थी कि वे महामारी की स्थिति के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक फाइल तक वास्तविक पहुंच से बचने के लिए जांच में भागीदार पक्षकारों के बीच ऐसे साक्ष्यों का आदान-प्रदान करें।
21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है।

22. इस तर्क के संबंध कि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार सौदे-वार आयात आंकड़ों की साफ्ट प्रति को सार्वजनिक फाइल में नहीं रखा गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी स्रोतों से आयात की मात्रा और मूल्य से संबंधित समेकित आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए हैं। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकार मांगने हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकृत किया है। हितबद्ध पक्षकारों को निदेशालय द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार आयात आंकड़े दिए गए हैं, ऐसे मामले में हितबद्ध पक्षकारों के साथ कोई पक्षपात हुआ, प्रतीत नहीं होता है।
23. विरोधी पक्षकार के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट को गोपनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना प्राथमिक रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रशासन से संबंधित है और उसे केवल शुल्क के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि ऐसी सूचना प्राप्त करने पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध हैं।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. विविध मुद्दों के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- यदि संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया तो प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता से अपनी अधिकांश जरूरतों की खरीद करनी पड़ेगी।
 - यद्यपि, याचिकाकर्ता पहले ही प्रयोक्ताओं को पीयूसी की आपूर्ति कर रहा है, तथापि जब आपूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो कच्ची सामग्री के विक्रेता में किसी परिवर्तन में काफी अधिक विनियमित भेषज उद्योग को देखते हुए सभी स्तरों पर भारी परिवर्तन करना अपेक्षित होता है।
 - विक्रेता में किसी परिवर्तन से नया विक्रेता अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करना अपेक्षित होगा जिसमें लगभग एक वर्ष लगता है। इसके अलावा, कच्ची सामग्री के विक्रेता में परिवर्तन के लिए प्रतिवादी उपभोक्ताओं को अपनी विनियामक फाइलिंग्स में स्रोत में परिवर्तन का उल्लेख करना होगा। विनियामक फाइलिंग्स में संशोधन में लगभग 6-7 महीने लग सकते हैं। विक्रेता बदलना अत्यंत कठिन है और यह समय और लागत खपाऊ प्रक्रिया है।
 - इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार बाजार स्थिति बन जाएगी क्योंकि याचिकाकर्ता ने भारत में पीयूसी का एकमात्र विनिर्माता होने का दावा किया है। इससे वर्तमान बाजार स्थिति, जहां प्रयोक्ता संबद्ध देश के पीयूसी के विभिन्न निर्यातकों पर विचार करते हुए प्रतिस्पर्धी कीमत पर आयात करने में सक्षम हैं, पूर्णतः बदल जाएगी।
 - घरेलू बाजार में कुल मांग और याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए चीन जन.गण. से आयात आवश्यक थे।
 - याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए स्थितियों को सिद्ध करने हेतु कोई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि जांचकर्ता प्राधिकारी ने संबंधित तथ्यों की समुचित, पर्याप्त जांच नहीं की है। वर्तमान जांच की शुरुआत पूर्णतः निराधार है और जांचकर्ता प्राधिकारी को वर्तमान जांच समाप्त कर देनी चाहिए।
 - याचिकाकर्ता को 2009-10 से क्षति हो रही है। यदि याचिकाकर्ता को संबद्ध देश से आयातों के कारण ऐसी गंभीर क्षति हुई थी तो उस समय वह प्राधिकारी के समक्ष क्यों नहीं आया। ऐसा लगता है कि कुछ अन्य कारण थे जिनकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई जिससे आगे वह रुग्ण इकाई बन गया तथा यह बात याचिका में नहीं बताई गई है।
 - प्राधिकारी से बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें कंपनी के रुग्ण होने का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को 2013-2016 के दौरान शटडाउन का सामना करना पड़ा और याचिकाकर्ता ने मैसर्स जेएम फाइनेशियल ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ हुए एक वित्तीय पुनर्गठन करार (पुनःस्थापन/पुनरुद्धार पैकेज) के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 से अपना उत्पादन पुनः शुरू किया है। ऋण एकत्र होना प्राथमिक रूप से अनुचित कीमत वाले आयातों और उसके परिणामी प्रभावों द्वारा सृजित प्रतिकूल व्यापार माहौल के परिणामस्वरूप हुआ था।
- ii. दिनांक 27.1.2016 को बीआईएफआर को संबोधित पत्र से यह स्पष्ट है कि कंपनी के प्रचालन चीन जन.गण. से बड़े पैमाने पर पाटन और बल्क औषधि उद्योग के लिए प्रतिकूल सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप कमतर कीमत मार्जिनों के कारण 1 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार, भूतकाल में हानिकारक पाटन, घाटे होने का प्रमुख कारण रहा है।
- iii. इसके अलावा, एसआईसीए, 1985 के अंतर्गत कंपनी के उल्लेख वाले बीआईएफआर के आदेश में 2004 में कंपनी के निवल मूल्य के सकारात्मक होने के बाद उसके संचयी घाटों के कारण के बारे में विशेष न्यायपीठ के एक प्रश्न के उत्तर में कंपनी का वक्तव्य दर्ज है। कंपनी के काउंसिल ने बताया कि कंपनी के लाभ कार्यशील पूंजी की कमी के कारण घट गए जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीन द्वारा औषधि और भेषज उत्पादों के भारी पाटन के कारण और अधिक गंभीर हो गए थे।
- iv. जेएमएफएआरसी ने याचिकाकर्ता की संभावनाओं को समझते हुए उसमें लंबे समय तक निवेश किया जिससे याचिकाकर्ता को अपना उत्पादन पुनः शुरू करने में मदद मिली। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की पूर्ववर्ती समस्याओं के आधार पर संबद्ध वस्तु के विश्वसनीय उत्पादक के रूप में उसकी निरंतरता संबंधी कोई भी आशंका इस स्तर पर निराधार है।
- v. याचिकाकर्ता पुनर्गठन के पश्चात विगत चार वर्षों से प्रचालन में है जो स्वयं दर्शाता है कि पुनरुद्धार विश्वसनीय था और ऋण सुबंधी मुद्दों को अब याचिकाकर्ता ने पीछे छोड़ दिया है।
- vi. अपने पूर्ववर्ती मुद्दों से भटकने के बाद याचिकाकर्ता ने निर्बाद पाटन और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के क्षतिकारी आयातों के विरुद्ध ही संवेदनशील है और पाटनरोधी शुल्क इसका सामना करने में आगामी समय में याचिकाकर्ता की मदद करेगा।
- vii. पुनरुद्धार पैकेज के बाद विगत चार वर्षों के दौरान कार्य-निष्पादन स्पष्ट रूप से पुनरुद्धार पैकेज की विश्वसनीयता को दर्शाता है और यह नोट किया जाए कि पुनरुद्धार पैकेज का लाभ याचिकाकर्ता को केवल तभी पूर्णतः प्राप्त हो सकता है जबकि चीन जन.गण. से एटीएस-8 के पाटन और क्षतिकारी आयात को रोकने के लिए पाटनरोधी उपाय लगाए जाएं और हम शीघ्रातिशीघ्र ऐसे उपायों की प्रार्थना करते हैं।
- viii. याचिकाकर्ता के पास अब भी लगभग 50 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है और मांग आपूर्ति में बताया गया अंतर वर्तमान मामले में एडीडी से वंचित रखने का कोई आधार नहीं है। इन तर्कों का कोई कानूनी या वास्तविक आधार नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।
- ix. यह सुस्थापित न्याय-शास्त्र है कि मांग-आपूर्ति का अंतर पाटित आयात को उचित नहीं ठहराता है और डीएसएम इडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट का निर्णय इस मामले पर भी लागू होता है। वर्तमान मामला मांग-आपूर्ति के अंतर का नहीं है बल्कि भारतीय उत्पादक द्वारा अपनी क्षमता का विवेकपूर्ण स्तर तक उपयोग करने में अक्षम होने के बारे में है।
- x. यद्यपि घरेलू उद्योग की *** एमटी की वर्तमान क्षमता पीओआई के दौरान पाई गई कुल भारतीय मांग तथा *** एमटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथापि घरेलू उद्योग ऐसी मांग के लगभग 50-60 प्रतिशत को पूरा कर सकता है किंतु मामले की सच्चाई यह है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का पीओआई के दौरान लगभग 40-50 प्रतिशत तक अल्प उपयोग हुआ था। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग की योजना मार्च, 2022 तक क्षमता को बढ़ाकर *** एमटी करने की है और घरेलू उद्योग बढ़ी हुई

क्षमता के साथ तत्पश्चात मांग के 80-90 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने में सक्षम होगा। क्षमता को बढ़ाने की योजना पटरी से उतर जाएगी, यदि पाटन को बिना कोई एडीडी लगाए निर्बाध रूप से जारी रखा जाता है।

- xi. डा. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आईक्यूआर दर्शाता है कि कंपनी ने 20.10.2021 को आईक्यूआर प्रस्तुत किया है जो प्राधिकारी द्वारा यह सूचना प्रस्तुत करने की समय-सीमा से काफी बाद में है। इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और उत्तर को अस्वीकार किया जाए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया है:

- i. इस तर्क के संबंध में कि यदि संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो प्रतिवादियों को अपनी अधिकांश जरूरत याचिकाकर्ता से खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए विक्रेता में भारी बदलाव जरूरी है, जिसकी काफी लम्बी प्रक्रिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश के आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है।
- ii. मांग-आपूर्ति में अंतर संबंधी दलील के संदर्भ में, वर्तमान मामले के तथ्यों से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान उत्पाद की मांग *** एमटी थी जबकि *** एमटी क्षमता के मुकाबले घरेलू उद्योग का उत्पादन *** एमटी था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के लगभग 40-50 प्रतिशत को पूरा करने की क्षमता है। यद्यपि, याचिकाकर्ता का उत्पादन पीओआई के दौरान, सूचित भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथापि, ऐसा संबद्ध देश से पाटन आयातों के कारण हो सकता है, फिर भी, मांग और आपूर्ति में अंतर क्षतिकारी पाटन आयातों के विरुद्ध उपचार की मांग करने से घरेलू उद्योग को वंचित नहीं कर सकता है।
- iii. इस तर्क के संबंध में कि एडीडी से याचिकाकर्ता का एकाधिकार हो जाएगा और ऐसा कोई उपाय जनहित के विरुद्ध होगा, यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से निर्मित उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप, इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, कोई पाटनरोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेष रूप से तब जब कि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके वितपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए स्थितियों को सिद्ध करने वाले कोई खास साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, यह नोट किया जाता है कि इस मामले को नियमावली के अंतर्गत यथा-अपेक्षित उन पर्याप्त साक्ष्यों को पूरा करने के बाद शुरू किया गया था जो जांच शुरुआत को उचित ठहराने के लिए उपलब्ध थे।
- v. इस तर्क के संबंध में कि डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड ने विलंब से आईक्यूआर प्रस्तुत किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आईक्यूआर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, उक्त पक्षकार के अनुरोधों पर उनकी इस जांच से संगत पाए जाने की सीमा तक विचार और समाधान करना प्रस्तावित है।
- vi. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता 2009-10 से क्षति उठा रहा है और प्राधिकारी को बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट से इस क्षति के कारणों की जांच करनी चाहिए, जिनमें कंपनी के रुग्ण बनने के कारण अवश्य बताए गए हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीआईएफआर रिपोर्ट का कंपनी की वित्तीय दशा के लिए विभिन्न मुद्दों जिनमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के भी होने का दावा किया गया है,

सहित अनेक मुद्दों का संज्ञान लिया गया है। वर्तमान जांच की क्षति अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और पीओआई है तथा वर्तमान जांच के दायरे में केवल इसी अवधि का घटनाक्रम शामिल है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिका, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात में भारी पाटन दर्शाती है और याचिका के अनुसार, पाटन मार्जिन 40-50 प्रतिशत के बीच है जो नियम के अंतर्गत अपेक्षित सीमा से अधिक और काफी अधिक भी है।
- ii. चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) और (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना गया है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में कार्य कर रहे हैं। चीन जन.गण. से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने लागू प्रश्नावली प्रस्तुत करके एनएमई मान्यता का खंडन नहीं किया है। अतः, चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।
- iii. याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करते हुए देश के लिए सामान्य मूल्य अनुमानित किया है क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर उत्पाद का सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध नहीं है। यह उत्पाद प्राथमिक रूप से भारत और चीन जन.गण. में उत्पादित होता है और किसी अन्य देश से भारत में कोई आयात नहीं हुआ है।
- iv. पाटन को भारतीय उत्पादन को पीयूसी के भारतीय उत्पादन आधार को बर्बाद करके एक रणनीति के रूप में अपनाया गया है और यह नोट किया जाना चाहिए कि चीन जन.गण. से आयात कीमत उत्पादन लागत से काफी कम है, जबकि घरेलू उद्योग की समायोजित उत्पादन लागत से काफी कम होने के कारण इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. डब्ल्यूटीओ ने चीन के एक्सेशन संबंधी प्रोटोकॉल के संगत प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी कार्यवाही में “प्रतिनिधि देश” प्रक्रिया 11 दिसंबर, 2016 से अनेक कानूनी आधारों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, ऐसी प्रक्रिया तत्पश्चात् अवश्य समाप्त होनी चाहिए।
- ii. निर्यातक यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि महानिदेशक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे के संबंध में चीन जन.गण. से निर्यातकों से काफी अधिक सूचना मांगते हुए चीन जन.गण. के निर्यातकों को एक अलग प्रश्नावली जारी की है। चीन जन.गण. को पूर्व में भारत द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
- iii. विश्व व्यापार संगठन में चीन जन.गण. के शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल का खंड 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। उस तारीख के बाद भारत के पास अब विश्व व्यापार संगठन के करारों के अंतर्गत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का प्रयोग करके चीन के उत्पादों की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य के परिकलन का कोई कानूनी आधार नहीं है।

- iv. प्राधिकारी चीन की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन.गण. को “बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा” प्रदान कर सकते हैं; पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई सामान्य मूल्य गणना कर सकते हैं; और कम कसे कम इस जांच में प्रतिनिधि देश के आंकड़ों को अपनाने के बजाए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कंपनी द्वारा अपने उत्तर में दिए गए लागत और कीमत आंकड़ों को अपना सकते हैं।
- v. पाटन मार्जिन को चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- vi. आवेदक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अन्तरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों की श्रेणी के अंतर्गत कटौतियों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- vii. याचिकाकर्ता ने कोई साक्ष्य दिए बिना गैर-वापसी योग्य वैट के समायोजन का यह कहते हुए दावा किया है कि चीन के निर्यातकों द्वारा सरकार को प्रदत्त वैट गैर-वापसी योग्य होता है। प्राधिकारी को याचिकाकर्ता और भागीदार चीन के निर्यातक से इस संबंध में साक्ष्य मांगना चाहिए।
- viii. याचिकाकर्ता ने 23.09.2021 को अद्यतन आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत की गणना करने का अनुरोध किया जाता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

29. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

30. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और प्रपत्र में सूचना देने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- (i) झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- (ii) झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- (iii) हांगझोऊ प्रोसेरे केमिकल कंपनी लिमिटेड

- (iv) जियांगसु युतियान फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- (v) जियांगसु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- (vi) जियांगसु पीफ्री फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

31. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: "गैट 1994 के अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) और एससीएम करार डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य ने चीन की मूलता वाले आयातों से संबंधित कार्यवाही पर निम्नलिखित के संगत लागू होंगे:

"क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताने समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, आरोहण नवाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में

दी जाने वाली सूचना/आंकड़े के माध्यम से भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अंतर्गत करना अपेक्षित है।

33. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
34. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि निर्यात कीमत के समायोजन साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए और यह कि पूरी पीओआई के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयातों पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समायोजनों की अनुमति प्रस्तुत साक्ष्यों की आवश्यक जांच के बाद दी गई है और संपूर्ण पीओआई के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है।

चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

35. चूंकि चीन जन.गण.से किसी भी उत्पादक ने ऊपर यथा-उल्लिखित अपने स्वयं आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश में उत्पाद की कीमत या परिकलित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि संगत सूचना न तो आवेदक के पास उपलब्ध है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार के पास और यह किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं था।
37. इसके अलावा, भारत में अन्य देशों से संबद्ध वस्तु का कोई आयात भी नहीं हुआ है और यह बताया गया है कि इस उत्पाद का प्राथमिक रूप से केवल भारत और चीन में उत्पादन होता है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य केवल भारत में प्रदत्त या देय कीमत को लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।
38. इस प्रकार, प्राधिकारी ने उत्पादन की ईष्टम लागत के आधार पर प्रमुख कच्ची सामग्रियों की कीमतों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भारत में प्रदत्त अन्य लागतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उत्पादन लागत में तर्कसंगत लाभ जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया है, और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

- क) मैसर्स जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लि., चीन जन.गण. और मैसर्स जियांग्सु पीफ़ि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

39. जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लि. ने पीओआई के दौरान भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है, जिसमें से *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात एक संबंधित व्यापारिक कंपनी अर्थात् जियांग्सु पीफ्री फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के ज़रिए किया गया है, जिसने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह भी नोट किया जाता है कि जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लि. ने दो असंबंधित व्यापारियों अर्थात् चाइना सिनोफार्म इंटरनेशनल कारपोरेशन और सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के ज़रिए भी भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और इन दो व्यापारियों ने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए इन दो व्यापारियों द्वारा भारत को निर्यातित मात्रा पर अंतिम निर्धारण में विचार नहीं किया गया।
40. जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ने वायु भाड़ा, वायु/समुद्री बीमा, अन्तरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार, समुद्री भाड़ा, कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ख) झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

41. झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है। यह सामान भारत में उपभोक्ताओं को सीधे बेचा गया है। उत्पादक/निर्यात ने पीओआई के दौरान ***अम.डॉलर बीजक मूल्य पर भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, अन्तरदेशीय परिवहन बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार इस प्रकार कारखानाद्वारा पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ग) मैसर्स झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और मैसर्स हांगझोऊ प्रोसेरे केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

42. झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है, जिसमें से एक असंबंधित व्यापारी अर्थात् हांगझोऊ प्रोसेरे केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के ज़रिए भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात हुआ है, जिसने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार इस प्रकार कारखानाद्वारा पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

घ) जियांग्सु युतियान फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

43. जियांग्सु युतियान फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है। यह सामान भारत में उपभोक्ताओं को सीधे बेचा गया है। उत्पादक/निर्यात ने पीओआई के दौरान ***अम.डॉलर बीजक मूल्य पर भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार इस प्रकार कारखानाद्वारा पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

चीन जन.गण. सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

44. चीन जन.गण. से सभी अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रस्तावित है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

45. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार प्रस्तावित है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य यूसडॉ./मी.टन	निबल निर्यात कीमत यूसडॉ./मी.टन	पाटन मार्जिन यूसडॉ./ मी.टन	पाटन मार्जिन%	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
2	झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
3	झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
4	जियांग्सु युतियान फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

46. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क्षति मापदंडों संबंधी सूचना इस तथ्य को दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में यथा-परिकल्पित वास्तविक क्षति हुई है।
- पाटित आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और ये घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई मात्रात्मक क्षति का कारण रहे हैं।
- आयात मात्रा में वृद्धि चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से कटौती का परिणाम थी।
- पाटित आयातों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का किसी तर्कसंगत स्तर तक कभी भी उपयोग नहीं कर सका और परिणामस्वरूप उसकी क्षमता का 50 प्रतिशत से अप्रयुक्त रहा और पीओआई और क्षति अवधि के दौरा अल्प-प्रयुक्त रहा। ऐसा तब हुआ जब उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई।
- पीओआई और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बीच आयातों में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी घाटा हुआ। यद्यपि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पीओआई में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में 996 के स्तर से घटकर 765 सूचीबद्ध बिंदु रह गया, तथापि पाटित आयातों का बाजार हिस्सा पीओआई में 75 सूचीबद्ध बिंदुओं से बढ़कर 82 बिंदु हो गया।
- निर्यातकों ने उत्पाद की कीमत को और घटाकर पीओआई में उच्चतर बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया और ऐसी लक्षित कार्यवाही से बाजार हिस्से के घाटे ने घरेलू उद्योग की मात्रात्मक वृद्धि को धीमा कर दिया जो मात्रात्मक क्षति से स्पष्ट है।
- यद्यपि क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री आदि जैसे मात्रात्मक मापदंडों में आधार वर्ष में सुधार हुआ, तथापि यह उल्लेखनीय है कि वास्तविक मात्रात्मक वृद्धि तब काफी अधिक और उत्कृष्ट होती, यदि पाटन नहीं होता।

- viii. पाटित आयातों के कारण मात्रात्मक क्षति बेकार अल्प-प्रयुक्त क्षमता की क्षति, बाजार हिस्सा गंवाने और मात्रात्मक मापदंडों में अल्प निष्पादन से प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग के पास और अधिक उत्पादन और बिक्री करने की क्षमता थी।
- ix. कीमत संबंधी क्षति मापदंड दर्शाते हैं कि ऐसी कीमत क्षति का आरंभिक कारण पाटित आयातों की पहुंच कीमत है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री कीमत (एनआईपी) से भी कम थी। घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा, जो आयात की पहुंच कीमत से कम थी तथा जो उसकी लागत से भी कम थी और उसे पीओआई के दौरान घाटा होता रहा है।
- x. निम्नोक्त जियोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट के आदेश के अनुसार यह सुस्थापित कानून है कि क्षति का निर्णय आदर्श स्थितियां मानकर नहीं लिया जा सकता है। परंतु प्रचलित दशाओं पर यह निर्णय करना होगा। यद्यपि तर्कसंगत समायोजन देखते हुए कानून की उक्त स्थिति के होते हुए भी याचिकाकर्ता ने कतिपय ब्याज मदों के लिए तर्कसंगत समायोजन करके अपनी लागत प्रस्तुत की है और यह देखा गया है कि पाटित आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन की ऐसी समायोजित लागत से अब भी कम रही है।
- xi. घरेलू उद्योग पीओआई में कोई तर्कसंगत आरओसीई प्राप्त नहीं कर सका है। घरेलू उद्योग के घाटे और अलाभकारी कीमत पाटित आयातों का सीधा परिणाम है।
- xii. नियम तथा प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कीमत क्षति दर्शाने के लिए कीमत कटौती सकारात्मक होनी चाहिए। नियम क अनुबंध II बताता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।
- xiii. घरेलू उद्योग पाटित आयातों की कम पहुंच कीमत के कारण अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर सका है और ऐसी पहुंच कीमत में उस कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती। कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण प्रभाव भी पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग अलाभकारी कीमतों पर बिक्री कर रहा था जो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है।
- xiv. तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान उत्पादन लागत में गिरावट आई, यद्यपि इसमें आधार वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग समान रही है।
- xv. घरेलू उद्योग की वृद्धि लगभग सभी मूल मापदंडों में नकारात्मक रही है और पीओआई के दौरान नकारात्मक वृद्धि पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट के साथ पीओआई के दौरान पाटित आयातों में वृद्धि का परिणाम थी।
- xvi. घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में दावे के अनुसार क्षति का कारण केवल पाटित आयात हैं। याचिका नियम के अनुसार तथा यूएस-हॉट रोलड स्टील मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय और जापान एडीडी मामले में व्याख्या के अनुसार भी कारणात्मकता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- xvii. जैसा दर्शाया गया है, आयातों की मात्रा और पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और पाटित आयातों के ऐसे प्रत्यक्ष परिणाम वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध दर्शाते हैं।
- xviii. पाटित आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान पाटित आयातों के हाथों बाजार हिस्सा गंवाया है और उसे पूरी क्षति अवधि में अपनी क्षमता का अल्प उपयोग करने को बाध्य होना पड़ा है। चूंकि तीसरे देशों से कोई आयात या देश में किसी अन्य उत्पादक से प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए यह नोट करना सही है कि घरेलू उद्योग द्वारा मात्रा संबंधी अल्प उपयोग और उठाई गई क्षति स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के कारण हुई है।

- xix. याचिकाकर्ता किसी अन्य कारक के कारण क्षति को शामिल नहीं करता है बल्कि क्षति के लिए केवल आयात जिम्मेदार हैं। यह दावा कि क्षति उच्च ब्याज और मूल्यहास के कारण हुई है, निरर्थक है।
- xx. पीओआई के दौरान ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यहास और कर भी नकारात्मक रहे हैं। ऐसी नकारात्मक स्थिति दर्शाती है कि ब्याज और मूल्यहास का क्षति के कारण होने का दावा निरर्थक है। अन्य पक्षकारों द्वारा यह दर्शाया नहीं गया है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।
- xxi. प्रतिवादी निर्यातकों के उत्तर से उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रमुख निर्यातक ने भारत को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में कीमत में भारी कटौती की है जो कीमतों को घटाए बिना संभव नहीं होता।
- xxii. वर्तमान क्षति की स्थिति के अलावा, याचिकाकर्ता पाटन और भविष्य में परिणामी क्षति के उच्चतर स्तर के गंभीर खतरे का सामना करता है और क्षति के आगे के खतरे के मद्देनजर एडीडी की तुरंत सिफारिश की जाए।
- xxiii. यहां पक्षकारों ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि पीओआई में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बढ़ती हुई मांग की स्थिति में भी पीओआई में 50 प्रतिशत भी नहीं था, जो पाटित आयातों के कारण स्पष्ट रूप से मात्रात्मक प्रभाव दर्शाता है। ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जिन्होंने मात्रात्मक वृद्धि के लिए चुनौती खड़ी की हो।
- xxiv. घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत, दोनों मोर्चों पर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में भारी गिरावट आई है और क्षमता उपयोग अत्यंत कम रहा था। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा और आरओसीई जांच अवधि तथा क्षति अवधि में नकारात्मक रहा है।
- xxv. यह तर्क कि घाटे ब्याज और मूल्यहास के कारण हुए हैं, निरर्थक है क्योंकि घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान पीबीटीआईडी (कर, ब्याज और मूल्यहास पूर्व लाभ) संबंधी घाटे भी हुए हैं। क्षमता बढ़ाने की योजना एक भावी निर्णय होता है जिसे उत्पाद के लिए बढ़ी हुई और भारी मांग के आधार पर लिया जाता है और उसका कार्यकरण उत्पाद के लिए अनुकूल माहौल पर निर्भर करेगा तथा ऐसी अनुकूल स्थिति केवल एडीडी लगाकर ही आ सकती है।
- xxvi. एटीएस-8 जिसमें अवांछित आइसोमर्स होते हैं, के शुद्धिकरण की दृष्टि से जॉब वर्क कुछ असंबंधित पक्षकारों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था जिसमें उक्त एटीएस-8 को उक्त पक्षकारों द्वारा आयातित समझा गया है। ये जॉब वर्क सौदे कैसे हुए इसका ब्यौरा याचिकाकर्ता के वित्तीय वर्णन के हिस्से में है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

47. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- याचिका में प्रदत्त सूचना वास्तविक क्षति उठाने संबंधी घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन नहीं करती है। संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि की अलग से जांच नहीं की जानी चाहिए बल्कि पीयूसी की मांग के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए।
- पीयूसी की कुल मांग में आधार वर्ष से पीओआई में 37 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई है जबकि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आयातों में केवल 12 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग अपने समस्त उत्पादन को बेचने में सक्षम है (बिक्री मात्रा और उत्पादन मात्रा पर आधारित) और केवल जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने पहली बार मालसूची दर्शाई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग बाजार मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है।
- घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश के आयात के बाजार हिस्से में परिणामी कमी आई है, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री में 923 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

- v. यद्यपि पीयूसी की मांग में 2018-19 में 113 सूचीबद्ध बिंदुओं की तुलना में 2019-20 में 101 सूचीबद्ध बिंदुओं की गिरावट आई है, तथापि घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2018-19 में 275 सूचीबद्ध बिंदुओं से 2019-20 में 996 सूचीबद्ध बिंदुओं की भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में इसी अवधि के दौरान 243 सूचीबद्ध बिंदुओं से 986 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई है। इस प्रकार घटती हुई मांग में भी घरेलू उद्योग ने आक्रामक रूप से बाजार हिस्सा प्राप्त किया है।
- vi. जब पीओआई में मांग में 137 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई तब घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां 1023 सूचीबद्ध बिंदुओं तक और अधिक बढ़ गई। यद्यपि, पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों में भी वृद्धि हुई है परंतु आयातों ने केवल भारत में मांग में वृद्धि और उसे पूरा करने में याचिकाकर्ता की क्षमता की प्रवृत्ति का पालन किया है।
- vii. उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के बारे में घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान अपनी क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम रहा है। अतः, उत्पादन के संबंध में कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- viii. खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के बारे में समग्र रूप से वृद्धि के बावजूद और भारत में मांग में वृद्धि होने पर भी आधार वर्ष के पश्चात खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।
- ix. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती नकारात्मक रही है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि घरेलू उद्योग ने आधार अवधि की तुलना में पीओआई में कीमत में 30 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि की है। अतः कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है।
- x. आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में कटौती को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में निरंतर और काफी अधिक बढ़ती रही है।
- xi. वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं है। घरेलू कीमतें पहुंच कीमत से स्वतंत्र चलती रही हैं।
- xii. स्थापित क्षमता में 2019-20 में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। जैसा बताया है, उक्त वृद्धि किसी नए पूंजीगत व्यय के कारण नहीं बल्कि पीयूसी के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों के अंतरण के कारण हुई है। इसके अलावा, 2022 तक क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। यदि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण वास्तव में क्षति हुई होती तो वह भविष्य में मौजूदा परिसंपत्तियों का अंतरण करने या नई क्षमता चालू करने में सक्षम नहीं होता।
- xiii. याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि बिक्री मात्रा और मूल्यों में पूरी क्षति अवधि में निरंतर और काफी अधिक वृद्धि हुई है। अतः इस संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है।
- xiv. याचिकाकर्ता ने स्वयं बताया है कि कर्मचारियों की संख्या और उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह माना गया है कि पीओआई तक मालसूची में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- xv. क्षति अवधि से पहले घरेलू उद्योग को बड़े वित्तीय धक्के झेलने पड़े थे, जिससे उनका निष्पादन प्रभावित हुआ। अतः क्षति अवधि के दौरान यद्यपि याचिकाकर्ता की स्थिति सुधर रही थी, तथापि उन्हें भारी घाटा हो रहा था। इन घाटों के कारणों को गहराई से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि ये घाटे वित्त लागत और मूल्यह्रास के कारण हुए थे जिनमें क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई थी।
- xvi. आधार वर्ष से वित्त लागत और मूल्यह्रास में क्रमशः 40 गुना और 20 गुना वृद्धि हुई है। इससे याचिकाकर्ता की समग्र लाभप्रदता में कमी आई है।
- xvii. पीओआई के दौरान केवल आरओसीई में औसत नियोजित पूंजी में कटौती के कारण भारी कमी आई है और ऐसा घाटों में वृद्धि की वजह से नहीं हुआ है।
- xviii. अनुबंध-II के पैरा (iv) में विहित अनिवार्य मापदंडों में से लगभग सभी मापदंडों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है। थाइलैंड-एच-बीम्स (डब्ल्यूटी/डीएस/122/आर) मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल का निर्णय यहां प्रासंगिक है।

- xix. संबद्ध आयातों और याचिकाकर्ता के आर्थिक कार्य-निष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। क्षति, यदि कोई हो, के लिए संबद्ध आयातों से इतर कारक जिम्मेदार हैं।
- xx. संबद्ध आयातों की मात्रा और याचिकाकर्ता के आर्थिक कार्य-निष्पादन के बीच कोई सह-संबंध नहीं होने जैसे कारकों, नकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण के अभाव से याचिकाकर्ता ने वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 और 2019-20 के दौरान सकारात्मक प्रचालन लाभ अर्जित किए हैं और समग्र घाटे केवल घरेलू उद्योग की उच्च वित्त लागत और मूल्यह्रास के कारण हुए हैं, जो कारणात्मक संबंध का अभाव दर्शाता है।
- xxi. स्टेनलेस स्टील 400 श्रृंखला के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों संबंधी रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि असामान्य रूप से उच्च मूल्य ह्रास और वित्त प्रभार कारणात्मक संबंध को समाप्त कर देते हैं।
- xxii. वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए याचिकाकर्ता के तुलन-पत्र का विश्लेषण दर्शाता है कि इक्विटी शेयर पूंजी और दीर्घावधिक उधार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, याचिका में इक्विटी और उधारियों में भारी वृद्धि देखी जा सकती है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सत्यापित करें कि याचिका के अनुसार पीयूसी के लिए निधियां कैसे आबंटित हैं जबकि याचिकाकर्ता के वित्तीय विवरणों के अनुसार उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
- xxiii. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। संबद्ध वस्तु की मांग में 100 (2016-17) से पीओआई के दौरान 137 तक की वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देश से आयात केवल 12 प्रतिशत अर्थात् 100 (2016-17) से पीओआई के दौरान 112 तक की वृद्धि हुई है जो मांग में वृद्धि से भी कम है।
- xxiv. उत्पादन और मांग की दृष्टि से आयातों में आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में पीओआई के दौरान तीव्र गिरावट देखी गई है। इस प्रकार, चीन जन.गण. से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- xxv. नकारात्मक कीमत कटौती इस तथ्य को दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयात कीमत से कम कीमत पर बेच रहा है। यदि घरेलू उद्योग कम लागत की वजह से घाटा झेल रहा है तो वह संबद्ध वस्तु की कीमत बढ़ा सकता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति के लिए संबद्ध देश से आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxvi. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल ऑफ सेट प्रिंटिंग प्लेटों के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के हाल में समाप्त हुए मामले में कीमत कटौती को एक महत्वपूर्ण मापदंड माना गया था और प्राधिकारी ने पीयूसी पर लागू एडीडी को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
- xxvii. ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने क्षति सिद्ध करने के लिए जान बूझकर आंकड़ों से छेड़छाड़ की है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त आंकड़ों तथा बिक्री मात्रा और बिक्री कीमत में कई गुना वृद्धि के बीच कोई सह-संबंध नहीं है, कंपनी की लाभप्रदता में तदनुसार सुधार होगा। तथापि, इसमें तेजी से गिरावट आई है जो संदिग्ध है। प्राधिकारी को इसकी गहराई से जांच करनी होगी।
- xxviii. ब्याज और वित्त लागत आधार वर्ष के दौरान 100 से असाधारण रूप से बढ़कर पीओआई के दौरान 4145 हो गई है। ऐसी अनियमित प्रवृत्ति मूल्यह्रास में वृद्धि में भी देखी जा सकती है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इसकी गहराई से जांच करें।
- xxix. आरओसीई में असामान्य प्रवृत्ति देखी गई है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इसकी गहराई से जांच करें।
- xxx. कंपनी एक रुग्ण इकाई के रूप में पूर्व में बंद रही थी और इसके कारण ने घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके लिए संबद्ध देश से पाटन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
49. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
50. यह भी नोट किया गया है कि ऊपर यथा-उल्लिखित विरोधी पक्षकारों के तर्क घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों से संबंधित हैं और ऐसे तर्कों पर क्षति मापदंडों की जांच करते समय यहां वस्तुतः विचार किया गया है और इसके मद्देनजर क्षति संबंधी तर्कों का संक्षिप्तता की वजह से अलग से समाधान नहीं किया जा रहा है।

झ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

51. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर विचार किया है। इस प्रकार आकलित मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
चीन जन.गण. से आयात	मी.टन	397	431	303	446
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	76	112
अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	Nil	Nil	Nil	Nil
देश में कुल आयात	मी.टन	397	431	303	446
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	273	1000	1027
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	101	137

52. जैसा उक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

53. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
चीन जन.गण. से आयात(संबद्ध देश)	मी.टन	397	431	303	446
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा	%	100	100	100	100
कुल आयातों में अन्य देशों का हिस्सा	%	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल	%	100	100	100	100

54. यह देखा गया है कि संबद्ध देश संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में समग्र रूप से आधार वर्ष में 397 मी.टन से पीओआई में 446 मी.टन की वृद्धि हुई है।

ग. सापेक्ष रूप से संबंध संबद्ध देश से आयात

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	397	431	303	446
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	101	137
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	273	1000	1045
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	75	82
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	8	11

55. यह नोट किया गया है कि भारतीय खपत और घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात में आधार वर्ष और पीओआई के बीच गिरावट आई है, तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में इसमें वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है, या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।

57. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच, कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

58. कीमत कटौती को संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना करके निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
निवल बिक्री प्राप्ति	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
रुझान		100	123	130	130
पहुंच कीमत	र./कि.ग्रा.	6,116	7,841	9,520	8,801
रुझान		100	128	156	144
कीमत कटौती	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

59. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक है, इसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पहुंच कीमत पीओआई सहित संपूर्ण क्षति अवधि में निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक रही है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

60. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमत का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में बदलाव को नोट करते हैं।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
बिक्री लागत	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	114	115
बिक्री कीमत	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	123	130	130
पहुंच कीमत	र./कि.ग्रा.	6,116	7,841	9,520	8,801
	सूचीबद्ध	100	128	156	144

61. यह देखा गया है कि बिक्री लागत 2017-18 से पीओआई तक 100 मूल बिंदुओं से बढ़कर 115 मूल बिंदु हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत 100 मूल बिंदु से बढ़कर 130 मूल बिंदु हो गई है और पहुंच कीमत इस अवधि के दौरान 100 से बढ़कर 143 मूल बिंदु हो गई है। यह भी नोट किया जाता है कि पहुंच कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।

iii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

62. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इन कारकों में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक या संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों की जांच शामिल होगी।

क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

63. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
स्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	223	223
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	273	1000	1045
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	278	456	478
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	273	1000	1027

64. यह नोट किया गया है कि क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
चीन जन.गण. से आयात	मी.टन	397	431	303	446
अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	Nil	Nil	Nil	Nil
देश में कुल आयात	मी.टन	397	431	303	446
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	273	1000	1027
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	101	137

निम्न के संबंध में भारतीय मांग में हिस्सा					
चीन जन.गण. से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	75	82
अन्य देशों से कुल आयात	%	Nil	Nil	Nil	Nil
देश में कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95.9	75.3	82
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	233	900	700
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	%	Nil	Nil	Nil	Nil

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के बाजार हिस्से में आधार वर्ष और 2019-20 के बीच गिरावट आई परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।

ग) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

66. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
बिक्री की लागत	सूचीबद्ध	100	124	114	115
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	123	130	130
लाभ/हानि	रु./मी.टन	***	***	***	***
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	-100	-126	-91	-94
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	-100	-347	-907	-960
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
नकद लाभ	सूचीबद्ध	-100	-351	-913	-929
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
पीबीआईटी	सूचीबद्ध	-100	-186	-389	-457
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
नियोजित पूंजी	सूचीबद्ध	100	112	248	253
आरओसीई	%	***	***	***	***
आरओसीई	सूचीबद्ध	-100	-165	-157	-186

67. यह नोट किया जाता है कि प्रति मी.टन घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ, पीओआई में नकारात्मक रहा था।

घ) रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	148	151
मजदूरी	रु. कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	226	730
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/ व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	672	692

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर, मजदूरी और उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कर्मचारियों की संख्या में किसी बड़े बदलाव के बिना पीओआई में मजदूरी में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने इसका कोई पर्याप्त औचित्य नहीं दिया है।

ड. पाटन मार्जिन की मात्रा

70. पाटन की मात्रा उस मात्रा का संकेतक है जिसमें भारत में आयात पाटित हुए हैं। जांच से पता चला है कि जांच अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

च) मालसूची

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
मालसूची	मी.टन				***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध				100

72. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष और 2019-20 के बीच घरेलू उद्योग की मालसूची में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तथापि, पीओआई में मालसूची में कुछ वृद्धि हुई थी।

छ) वृद्धि

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा जैसे मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है परंतु बाजार हिस्सा और लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय जैसे कीमत मापदंड पीओआई के दौरान नकारात्मक रहे हैं, जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पीओआई)
उत्पादन	%	-	172.73	266.67	4.55
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	172.73	266.67	2.73

क्षमता उपयोग	%	-	177.78	64.00	4.88
बाजार हिस्सा	%	-	142.98	305.94	-22.44
प्रति कि.ग्रा. बिक्री की कीमत	%	-	22.95	5.76	-0.14
प्रति कि.ग्रा. बिक्री की लागत	%	-	241.29	233.98	3.64
लगाई गई पूंजी पर आय	%	-	-65.46	5.33	-18.84
प्रति इकाई लाभ	%	-	-26.28	27.91	-3.10
प्रति यूनिट पीबीआईटी	%	-	-85.82	-109.09	-17.72
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	%	-	166.67	168.75	4.65

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु पूंजी निवेश किया है और घरेलू उद्योग को क्षति अवधि से पहले शटडाउन का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान पुनर्गठन के भाग के रूप में नए पूंजी निवेश के साथ उत्पादन शुरू किया है।

झ) क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री की मात्रा

75. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त और जांच अवधि के लिए कार्यरत लागत लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के साथ भी यही पद्धति अपनाई गई है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभावित न किए जाएं। प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए उत्पादन लागत की गणना से संबंधित व्यय के कार्य को बाहर रखा है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध -III में यथा विहित ब्याज, कारपोरेट कर और लागत की वसूली के लिए एक तर्कसंगत आय (कर-पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई है और पालन किया गया है।
76. संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
77. ऊपर यथा-निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

क्षति मार्जिन

देश	उत्पादक/ निर्यातक	एनआईपी (यूएसडॉलर/ एमटी)	पहुंच मूल्य (यूएसडॉलर/ एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉलर /एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रैंज)
चीन जन.गण.	जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
चीन जन.गण.	झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10

चीन जन.गण.	झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
चीन जन.गण.	जियांग्सु युतियान फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
चीन जन.गण.	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

I गैर-आरोपण विश्लेषण

78. एडी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात कार्य-निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(i) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

79. देश से इतर किसी देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है।

(ii) निर्यात निष्पादन

80. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

(iii) मांग में संकुचन/खपत के पैटर्न में बदलाव

81. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

(iv) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

82. संबद्ध वस्तु के आयात किसी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं कोई परिवर्तन हुआ है।

(v) प्रौद्योगिकी में विकास

83. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी खास बदलाव दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(vi) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

84. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत में आयातित संबद्ध वस्तु तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन वस्तुओं को प्रतिस्थापनीय मानते हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा खपत के पैटर्न में परिवर्तन दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(vii) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए और अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन संबद्ध वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग के निष्पादन के प्राधिकारी द्वारा आकलन को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद संबंधी सूचना पर विचार किया गया है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

86. प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

87. प्राधिकारी ने 18.07.2022 को हितबद्ध पक्षकारों के लिए इस जांच में अनिवार्य तथ्यों वाला प्रकटन विवरण जारी किया और हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणियां देने के लिए 22.07.2022 तक का समय दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर उनके संगत होने की सीमा तक निम्नानुसार विचार और जांच की गई है:

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

88. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. संबद्ध वस्तुओं का भारत के लिए काफी अधिक महत्व है और इन पर पाटनरोधी शुल्क लागू करना जनहित के लिए नुकसान दायर होगा।
- ii. भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि बहुत कम है और पाटनरोधी शुल्क लगाने को उचित नहीं ठहराती है।
- iii. संपूर्ण क्षति अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक रही है क्योंकि संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य इस पूरी अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक रहा है। प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि क्यों नहीं कर सका था क्योंकि यह स्वयं पहुंचाई गई क्षति का मामला लगता है।
- iv. घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों को देखने से पता चलता है कि वह 2018-19 से लाभ में चल रहे हैं परंतु काफी अधिक ब्याज लागत और मूल्यहास तथा परिशोधन लागत के समायोजन के बाद घाटे में आ गया है।
- v. इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के नकद प्रवाह के विवरण से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सकारात्मक प्रचालन नकद प्रवाह अर्जित कर रहा है।
- vi. केवल उच्च ब्याज लागतों से ऐसा हुआ है कि याचिकाकर्ता क्षति उठा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने स्वयं वित्तीय लागत को एमसीए में दायर वित्तीय विवरणों में प्रचालन लागत का भाग नहीं माना है। इसलिए, प्राधिकारी को यही नीति अपनानी चाहिए और पीयूसी की लाभप्रदता के विश्लेषण के समय ब्याज की अनदेखी करनी चाहिए।
- vii. लाभों में अत्यधिक आय को थोड़ा शामिल करने के कारण काफी अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अन्य खर्चों में कुछ आपवादिक खर्च हैं। याचिकाकर्ता ऐसी आपवादिक मदों को हटाने के बाद भी लाभ कमा रहा है। इसे नीचे तालिका में स्पष्ट किया गया है।
- viii. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पीओआई के दौरान वास्तव में लाभ कमाया है और केवल आपवादिक आय शामिल करने के कारण नहीं। अतः, संबद्ध आयात और याचिकाकर्ता के निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग का परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत असामान्य ब्याज लागत, मूल्यहास और परिशोधन लागत तथा मजदूरी लागत को समायोजित करने के बाद निर्धारित की जानी चाहिए। ये समायोजन किए बिना पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक और अनुचित होगा।
- x. पीयूसी की लागत अटोरावेस्टेटिन एपीआई बल्क ड्रग के निर्माण की कुल लागत का लगभग 30-35 प्रतिशत है। इसके अलावा, पीयूसी की लागत अटोरावेस्टेटिन एपीआई बल्क ड्रग की बिक्री कीमत का 18-23 प्रतिशत है। डॉ. रेड्डी ने उक्त आंकड़ों के समर्थन में रिकॉर्ड में साक्ष्य दिए हैं। इसके अलावा, हमारे अनुमान में पीयूसी की लागत में अटोरावेस्टेटिन नुस्खे/टेबलेट की लागत का लगभग 15-20 प्रतिशत बनता है। इस प्रकार, 20-30 प्रतिशत के पाटनरोधी शुल्क का डॉ. रेड्डी और अमोली की लाभप्रदता पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, कच्ची सामग्री के विक्रेता में किसी परिवर्तन में काफी अधिक विनियमित भेषज उद्योग पर विचार करते हुए सभी स्तरों पर भारी बदलाव की जरूरत होती है।

- xi. संबद्ध वस्तु की कीमत काफी स्थिर है। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं तो घरेलू उद्योग और प्रयोक्ताओं के हित को संतुलित करने के लिए प्राधिकारी शुल्क के संदर्भ कीमत रूप की कृपया सिफारिश करें।
- xii. प्राधिकारी को इस मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए “प्रतिनिधि देश” पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। प्राधिकारी को घरेलू बिक्री या लागत के होंगयुआन फार्मास्युटिकल पर आधारित पाटन मार्जिन का परिकलन करना चाहिए।
- xiii. सामान्य मूल्य और एनआईपी की गणना में प्रयुक्त आंकड़े अत्यधिक संरक्षित हैं, जिनके कारण होंगयुआन फार्मास्युटिकल सार्थक और कारगर टिप्पणियां नहीं दे पाया।
- xiv. चीन जन.गण. से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- xv. एनआईपी की गणना में प्रयुक्त 22 प्रतिशत आरओसीई उचित नहीं है और उसे संशोधित करना चाहिए।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

89. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी काफी कम है और तथ्यों को उचित ढंग से समझकर, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कम एनआई के कारण कम क्षति मार्जिन से उन निर्यातकों को लाभ होगा जो पाटन में शामिल हैं।
- ख) कम एनआईपी से एडीडी का पाटन के विरुद्ध संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी। एनआईपी निर्धारण संबंधी निम्नलिखित चिंताओं का अंतिम जांच में कृपया समाधान किया जाए;
 - i. प्राधिकारी ने टिप्पणियों में तालिकाबद्ध घरेलू उद्योग के मुख्य खर्चों के कुछ दावों की अनुमति नहीं दी है। दिनांक 21 जुलाई, 2022 के ईमेल द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग गया था, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है और न्याय न मिलने से बचने के लिए जांच परिणाम जारी होने से पहले यह स्पष्टीकरण कृपया दिया जाए, ऐसे स्पष्टीकरण के बिना समय पर टिप्पणियां जांच में किसी देरी से बचने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।
 - ii. प्रकटन में एनआईपी के निर्धारण में वेतन और मजदूरी के आबंटन के आधार को युक्तिसंगत और तर्कसंगत बनाने के लिए बदला जाना चाहिए। उत्पादन मात्रा के बजाए वर्तमान मामले के विचित्र तथ्यों में विभाजन के आधार पर मशीन घंटों पर विचार किया जाना चाहिए।
 - iii. कंपनी ने मदर लिकर के साथ सक्रिय बनाकर एटीएस-8 को शुद्ध करने का कुछ जॉब बर्क किया है और इस प्रक्रिया में केवल 0.19 प्रतिशत कुल मशीन घंटे लगे हैं। तथापि, यदि ऐसे जॉब बर्क को उत्पादन कार्यकलाप माना जाता है तो ऐसा जॉब बर्क कुल उत्पादन मात्रा का 58.48 प्रतिशत बनता है जिससे लागत विभाजन के समय वेतन और मजदूरी का बड़ा हिस्सा जॉब बर्क में चला जाता है।
 - iv. यह प्रश्न कि 0.19 प्रतिशत मशीन घंटे लागत निर्धारण में वेतन और मजदूरी का 58.48 प्रतिशत हिस्सा कैसे ले लेते हैं, केवल यह दर्शाता है कि अपनाई गई पद्धति में कुछ अन्तरनिहित गलतियां हैं।
 - v. नियमावली के अनुबंध-III के पैरा VI में अपेक्षित है कि विभाजन का आधार तर्कसंगत और वैज्ञानिक होना चाहिए। तत्पश्चात एक सांकेतिक आधार निर्धारित किया गया और मशीन घंटों से शुरू होकर एक अनुक्रम निर्धारित होना स्पष्ट है और यह क्रम चल रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध के अनुसार वेतन और मजदूरी के विभाजन के आधार के रूप में मशीन घंटे नियमानुसार उपयुक्त हैं और वर्तमान मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि यह पद्धति पूर्णतः तर्कसंगत और वैज्ञानिक है तथा मशीन घंटे के ब्यौरे भी उपलब्ध हैं।

- vi. नियमावली का अनुबंध-III नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय का घरेलू उद्योग की एनआईपी निर्धारित करते समय प्रावधान करता है किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों में नकारात्मक आय पर विचार दर्शाया गया है जो नियम का लक्षित उद्देश्य नहीं है।
- vii. पैरा IX के साथ पठित अनुबंध-III के पैरा VIII के अनुसार ब्याज की अनुमति बिक्री लागत की एक मद के रूप में है। इसलिए, पैरा IX के आधार पर तर्कसंगतता परीक्षण के पश्चात ब्याज लागत की बिक्री लागत के रूप में अनुमति देनी होगी। पैरा VIII में यह निर्धारण कि आय की शेष राशि को क्षति रहित कीमत ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में माना जाएगा, स्पष्ट रूप से शेष राशि के बारे में केवल सकारात्मक गणना/समझ के रूप में बात करता है क्योंकि किसी नकारात्मक राशि से कर-पूर्व लाभ नहीं हो सकता है।
- viii. यह समझा गया है कि प्राधिकारी ने एनआईपी की गणना में वास्तव में 5 प्रतिशत से कम की परिकलित आय के मामले में न्यूनतम 5 प्रतिशत की अनुमति दी है और तर्कसंगत आय सुनिश्चित करने की ऐसी पद्धति को नकारात्मक परिदृश्य में भी माना जाना चाहिए।
- ix. वास्तव में, घरेलू उद्योग को पहले आबंटन के आधार को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं मिला क्योंकि विभाजन के आधार पर त्रुटि केवल संबद्ध प्रकटन विवरण की प्राप्ति के बाद ही स्पष्ट हुई है। तथापि, यह महसूस किया गया है कि प्रकटन विवरण के स्तर पर टिप्पणियां आबंटन के आधार को स्पष्ट करने के लिए विलंब से नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने मशीन घंटे आदि के ब्यौरे सहित आबंटन का आधार निर्धारित करने के लिए समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की।
- x. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में पीयूसी और समान वस्तु संबंधी अपने प्रस्तावों की पुष्टि कर सकते हैं।
- xi. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के पहलू संबंधी अपने प्रस्तावों की पुष्टि कर सकते हैं।
- xii. प्राधिकारी एनआईपी के निर्धारण हेतु भरोसा की गई लागत पर हमारी टिप्पणियों पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारण पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह महसूस किया गया है कि झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के मामले में पाटन मार्जिन भी काफी अधिक है।
- xiii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी स्पष्ट है।
- xiv. घरेलू उद्योग को पाटन आयातों की पहुंच कीमत के कारण पड़े कीमत प्रभाव के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं और मात्रात्मक मापदंड भी भारतीय बाजार में पाटन आयातों की भारी मौजूदगी के कारण मानक स्तर से कम रहे हैं। पाटन आयातों का काफी अधिक बाजार हिस्सा रहा है।
- xv. इस मामले में पाटन के प्रभाव को सुधारने के लिए पाटनरोधी शुल्क की स्पष्ट आवश्यकता है।
- xvi. यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि क्षति अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक थी, तथापि यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। स्पष्ट रूप से पाटन आयातों ने ऐसी कीमत वृद्धि को रोका था जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। ऐसी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से भी कम है और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है।
- xvii. घरेलू उद्योग इस बात से वास्तव में चिंतित है कि झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के मामले में क्षति मार्जिन नकारात्मक है और अन्य दो प्रतिवादी निर्यातकों के लिए मार्जिन काफी कम है। ऐसे कम मार्जिन का कारण स्पष्ट रूप से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम एनआईपी है और ऐसे सभी निर्यातकों से आयात भारत में काफी कम कीमत पर पहुंच रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत प्रभाव है। प्राधिकारी एनआईपी की गणना संबंधी हमारी टिप्पणियों के आधार पर क्षति मार्जिन गणनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

- xviii. यह दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता के अनुमानों के अनुसार एटीएस-8 का एटोरावेस्टेटिन ड्रग की लागत में 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत का मामूली हिस्सा बनता है और किसी एडीडी से अंतिम औषधि पर केवल बिल्कुल मामूली प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ऐसी औषधि में मध्यवर्ती वस्तु की लागत अत्यंत कम है। एडीडी के कारण आम जनता पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ एडीडी से घरेलू उद्योग की निरंतर मौजूदगी सुनिश्चित होगी जिससे अन्ततः भारत में प्रयोक्ताओं को लाभ होगा।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की गई टिप्पणियां/अनुरोध अधिकांशतः उनके पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्तियां हैं, जिनकी पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है और प्रकटीकरण विवरण में या वर्तमान जांच परिणाम के संगत पैरा में समुचित रूप से उनका समाधान किया जा चुका है। प्राधिकारी ने जहां तक ये अनुरोध संगत पाए गए और अन्यत्र इनका समाधान नहीं किया गया है, उनकी नीचे दिए गए अनुसार जांच की है, जो इस प्रकार है :-
- प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है।
 - प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की लाभप्रदता पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी पुनः दोहराते हैं कि यद्यपि एटोर्वास्टेटिन एपीआई ब्लक ड्रग के निर्माण में विचाराधीन उत्पाद की लागत प्रदान की गई है, लेकिन ड्रग की अवस्था में आगे लागत वृद्धि हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। ऐसी सूचना के अभाव में, एटोर्वास्टेटिन टेबलेट की लागत पर विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।
 - जहां तक आवेदन के आधार को स्पष्ट करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अवसर के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा अपने एनआईपी दावे में बार-बार परिवर्तन का अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया गया था। आंकड़ों के सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग को आबंटन का आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया था।
 - घरेलू उद्योग द्वारा वेतन और मजदूरी के संबंध में तर्क के बारे में, प्राधिकारी ने निम्नलिखित आंकड़ों को नोट किया है :-

(स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत फार्मेट-एच और फार्मेट-सी)

विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए/दावा किए गए मापदंड					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (जांच की अवधि)
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दावा की गई वेतन एवं मजदूरी लागत	लाख रु.	***	***	***	***
विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दावा की गई वेतन एवं मजदूरी लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
विचाराधीन उत्पाद की उत्पादकता	कि.ग्रा./कर्मचारी	***	***	***	***
कंपनी के लिए समग्र वेतन व मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***

विचाराधीन उत्पादन	सूचीबद्ध	100	273	1000	1045
कर्मचारियों की संख्या	सूचीबद्ध	100	115	148	151
विचाराधीन उत्पाद के लिए दावा की गई वेतन एवं मजदूरी लागत (लाख रु. में)	सूचीबद्ध	100	435	2283	7726
विचाराधीन उत्पाद के लिए दावा की गई वेतन एवं मजदूरी लागत (रु./कि.ग्रा.)	सूचीबद्ध	100	157	225	731
विचाराधीन उत्पादकता (कि.ग्रा./कर्मचारी)	सूचीबद्ध	100	238	668	688
कंपनी के लिए समग्र वेतन एवं मजदूरी (लाख रु. में)	सूचीबद्ध	100	131	127	152

यह नोट किया गया था कि :

- क. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 4(vi) के तहत यह प्रावधान है कि "उत्पाद के लिए अभिज्ञात किए गए व्यय सीधे आबंटित किए जाने हैं और फैक्ट्री के तहत वर्गीकृत साझा व्यय अथवा ओवरहेड, प्रशासनिक और बिक्री ओवरहेड को तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर पृथक किया जाए, जैसे मशीन के घंटे, पात्र अधिभोग घंटे, श्रम घंटे, उत्पादन की मात्रा, बिक्री मूल्य इत्यादि, जो घरेलू उत्पादकों द्वारा निरंतर प्रयोग में लाए जाते हैं और जांच की अवधि के दौरान दावा किए गए विभिन्न व्ययों की तर्कसंगतता और स्पष्टीकरण की जांच की जाए तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में अनुरूपी धनराशि के साथ तुलना करके जांच पड़ताल की जाए।"
- ख. उपरोक्त तालिका में यथा-उल्लिखित तत्काल पूर्व के वर्ष के दौरान अनुरूपी धनराशि के साथ ऐसी तुलना पर, यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादकता में 13 आधार प्वाइंट तक की वृद्धि हुई है, कंपनी की वेतन लागत में 25 आधार प्वाइंट तक की वृद्धि हुई है, जबकि विचाराधीन उत्पाद के लिए दावा की गई वेतन लागत लाख रु. में और रु./कि.ग्रा. में क्रमशः 5543 आधार प्वाइंट और 506 आधार प्वाइंट तक की वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग विगत वर्ष/आईआईपी (2019-20) की तुलना में जांच की अवधि (2020-21) में वेतन लागत में वृद्धि के बारे में सहायक दस्तावेजों का तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करने में समर्थ नहीं था, जब कर्मचारियों की संख्या में कोई पर्याप्त बदलाव और विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा में बदलाव नहीं था।
- घ. इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा दावा वेतन और मजदूरी आबंटन के संबंध में अपनाई गई आबंटन कार्य-विधि अर्थात् विगत वर्षों/क्षति जांच अवधियों के दौरान आवेदक द्वारा अपनाई गई आबंटन कार्य-विधि के अनुरूप है।
- v. जाँच कार्य के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग के आवेदन में और न ही कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण में, जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए ऐसे किसी जाँच कार्य के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरे, घरेलू उद्योग इस संबंध में कोई समझौता ज्ञापन या कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावे और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उत्पादन और बिक्रियों पर विचार किया है।
- vi. एनआईपी की गणना करते समय, नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III (viii) में यह प्रावधान है कि "ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (कर पूर्व) की अनुमति दी जाएगी।" डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार नियोजित औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल प्रदान किया गया है। इस प्रकार से प्रदान किए गए 22 प्रतिशत प्रतिफल में ब्याज लागत, कर और लाभ शामिल हैं।

- vii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की अधिक वित्त लागत को ध्यान में रखा है। इस पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि निवल आय में गिरावट ब्याज के अधिक प्रावधान के कारण है। अतः इस सीमा तक क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- viii. अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा परिकलित एनआईपी के संबंध में प्रकटीकरण विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों/ तर्कों में कोई दम नहीं है।
- ix. निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण, तर्कसंगत लाभों को जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री सामान्य व प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर भारत में वास्तव में भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर लिया गया है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

91. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के पहलुओं पर हितबद्ध पक्षकारों और याचिकाकर्ता के विभिन्न अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार और जांच की गई है:

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. पीयूसी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा।
- ii. तैयार एटोरवेस्टेटिन नुस्खे की कीमत औसत (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 द्वारा नियंत्रित होती है और लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, का बोझ प्रतिवादियों को झेलना पड़ेगा।
- iii. एक आवश्यक वस्तु होने के कारण एटोरवेस्टेटिन नुस्खे की कीमत डीपीसीओ द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित तालिका डीपीसीओ के अनुसार एटोरवेस्टेटिन नुस्खे की कीमत दर्शाती है:

विवरण	दिनांक 25.03.2020 के आदेश के अनुसार 01.04.2020 से प्रति टेबलेट अधिकतम कीमत	दिनांक 25.03.2021 के आदेश के अनुसार 01.04.2021 से प्रति टेबलेट अधिकतम कीमत
एटोरवेस्टेटिन- 10एमजी	5.47	5.50
एटोरवेस्टेटिन- 20एमजी	13.25	13.32
एटोरवेस्टेटिन- 40एमजी	19.24	19.34
स्रोत: दिनांक 25.03.2020 और 25.03.2021 के आदेश जिनमें डीजीसीआई के अनुसार अधिकतम कीमत तय की गई है।		

- iv. डीपीसीओ के अनुसार कीमत वृद्धि भी अत्यंत कम है और 2020 से 2021 के लिए 0.53568 प्रतिशत के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है।
- v. जब इस नुस्खे की कीमत डीपीसीओ द्वारा नियंत्रित होती है तो प्रतिवादी एपीआई की कीमत में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं थे। इसी के साथ प्रतिवादी पीयूसी के प्रयोक्ता है और इसलिए उन्हें पाटनरोधी शुल्क, यदि लगाया गया, के माध्यम से पीयूसी की कीमत वृद्धि को झेलना पड़ेगा।
- vi. एटोरवेस्टेटिन टेबलेट 5 एमजी एक आवश्यक वस्तु नहीं है और डीपीसीओ द्वारा नियंत्रित नहीं है। तथापि, एटोरवेस्टेटिन नुस्खे के समग्र बाजार में इसका बाजार हिस्सा काफी कम है। अधिकांश बाजार 10 एमजी, 20 एमजी और 40 एमजी की टेबलेट का है, जिसे डीपीसीओ के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है।

- vii. पीयूसी की लागत में लगभग [30 प्रतिशत – 40 प्रतिशत] एटोरवेस्टेटिन एपीआई की लागत होती है। इसके अलावा, पीयूसी की लागत में लगभग [5 प्रतिशत – 15 प्रतिशत] एटोरवेस्टेटिन नुस्खे की लागत होती है। डॉ. रेड्डी एटोरवेस्टेटिन एपीआई का निर्माण और बिक्री करता है, अमोली आर्गेनिक एटोरवेस्टेटिन एपीआई का निर्माण और बिक्री करता है। इस प्रकार, 20-30 प्रतिशत के पाटनरोधी शुल्क से प्रतिवादियों की लाभप्रदता पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा और इसके प्रतिवादियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।
- ix. पीयूसी का प्रयोग एटोरवेस्टेटिन टेबलेट बनाने में किया जाता है जो एक जीवन-रक्षक दवाई है तथा जिसे कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने में प्रयोग किया जाता है। कोविड-19 महामारी के आरंभ में विभिन्न साइड इफेक्ट हुए थे, जिनमें से इससे ठीक होने वाले अनेक लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी बढ़ गया था। कोविड-19 महामारी के कारण कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से निपटने के लिए एटोरवेस्टेटिन एक औषधि है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग का अस्तित्व व्यापक जनहित के लिए आवश्यक है और जनहित का उल्लेख करके एडीडी का विरोध केवल एक भ्रामक बात है जिसे निर्यातकों द्वारा पाटन का फायदा उठाने के लिए बताया जा रहा है।
- ii. एटीएस-8 एक भेषज मध्यवर्ती है जिसका एटोरवेस्टेटिन एपीआई के उत्पादन में प्रयोग होता है और इसे मानव के कैलोस्ट्रॉल को घटाने के लिए एटोरवेस्टेटिन नुस्खों/दवाईयों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और इस महत्वपूर्ण भेषज मध्यवर्ती वस्तु की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता की मौजूदगी अनिवार्य होगी। अन्यथा, देश एटीएस-8 के लिए चीन जन.गण. से आयातों पर निर्भर हो जाएगा जो किसी भी तरह से जनहित में नहीं हो सकता है।
- iii. याचिकाकर्ता के उत्पादन और आपूर्ति के अभाव में भारत में प्रयोक्ता केवल चीन जन.गण. से आयातों पर निर्भर हो जाएंगे और इससे कीमत और मात्रा दोनों की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- iv. प्रयोक्ताओं को पाटित आयातों पर आधारित अल्पावधिक लाभ मिल सकता है परंतु भारत में उत्पाद की कोई घरेलू आपूर्ति न होने पर और आयातों के भारतीय बाजार में एकाधिकार स्थापित करने पर कीमत में अयुक्तिसंगत वृद्धि हो सकती है।
- v. विरोधी पक्षकारों ने अंतिम विनिर्मिति पर किसी एडीडी के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। दावों को सिद्ध करने के लिए लागत और कीमत के कोई वास्तविक ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। संबद्ध वस्तु पर किसी एडीडी से एटोरवेस्टेटिन नुस्खे पर काफी नगण्य कीमत प्रभाव पड़ेगा और एटोरवेस्टेटिन एपीआई के उत्पादक और नुस्खे के उत्पादक एटीएस-8 पर लागू किए जाने वाले किसी एडीडी के कारण ऐसी मामूली कीमत वृद्धि को पास करने में सक्षम होंगे।
- vi. याचिकाकर्ता के अनुमान के अनुसार, एटीएस-8 एटोरवेस्टेटिन औषधि की लागत का केवल 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत हिस्सा हो सकता है और किसी एडीडी से अंतिम औषधि पर बिल्कुल मामूली प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ऐसी दवाई में मध्यवर्ती वस्तु की लागत काफी कम होती है। एडीडी के कारण आम जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- vii. यह दलील दी गई है कि एडीडी लगाने से एटोरवेस्टेटिन एपीआई विनिर्माताओं की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत में एटोरवेस्टेटिन नुस्खे के लिए उद्योग की कीमत औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 द्वारा विनियमित होती है। यह दलील पूर्णतः निराधार है और यथा-आरोपित नुस्खे पर प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- viii. डीपीसीओ के अंतर्गत विनियम गतिशील कीमत निर्धारण तंत्र हैं और एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ के अंतर्गत निर्धारित कीमतों में उत्पाद की निविष्टि लागत और तर्कसंगत लाभ पर भी विचार किया जाता है और ये कीमतें निविष्टि लागत आदि में किसी वास्तविक बदलाव के आधार पर परिवर्तनों के अधीन होती हैं। उत्पाद पर एडीडी का डीपीसीओ के अंतर्गत कीमत विनियमन के लिए विचारित उचित निविष्टि लागत पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- ix. इसके निर्माता यथा-आरोपित किसी ढंग से नुकसान नहीं उठाएंगे और यह दलील केवल प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास है। यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि एडीडी से कुछ अंतिम प्रयोक्ताओं की लागत पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा परंतु एडीडी को सदैव पाटन के क्षतिकारी प्रभावों को समाप्त करने के उपाय के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसका दायरा इतना ही होता है। एडीडी केवल कीमत विकृति को रोकेंगे और इससे परस्पर कीमत वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- x. कीमत विनियम अंतिम नुस्खे के लिए है जिसमें संबद्ध वस्तु केवल एक मध्यवर्ती वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु के उत्पादक द्वारा उस पर पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण की मांग करने में पाटनरोधी नियम के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लाकलेजाइड से संबंधित एडीडी जांच जैसे मामलों में प्राधिकारी ने पहले ऐसे मुद्दों का समाधान किया है और वर्तमान मामले में भी यही विचार अनिवार्य है।
- xi. उत्पाद के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने हेतु एडीडी को जनहित के विरुद्ध उपाय नहीं माना जा सकता है और वर्तमान मामले में एडीडी आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा भारत में एटीएस-8 के उत्पादक के हितों के बीच केवल उचित संतुलन बनाने के लिए होगा।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की प्रक्रिया से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- 93. प्राधिकारी विचार करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी जांच करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर शुल्क लगाने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ता तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और सामान्य जनता पर प्रभाव की जांच की है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित करने का प्रस्ताव है।
- 94. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाने हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क से उनके प्रचालनों पर किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। वर्तमान जांच में भाग लेने वाले दो प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर भी उनके साक्ष्य द्वारा समर्पित होने की सीमा तक विचार किया गया है।
- 95. इस तर्क के संबंध में कि एक अनिवार्य वस्तु होने के कारण एटोरवेस्टेटिन नुस्खे की कीमत डीपीसीओ द्वारा नियंत्रित होती है और किसी एडीडी से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और अंतिम प्रयोक्ताओं पर ऐसे कीमत नियंत्रण के कारण काफी प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध उत्पाद एक भेषज मध्यवर्ती वस्तु है जो एटोरवेस्टेटिन एपीआई के उत्पादन में प्रयुक्त होती है तथा जिसे आगे एटोरवेस्टेटिन नुस्खे/दवाई में प्रयोग किया जाता है। डीपीसीओ द्वारा यथा-निर्धारित कीमत अंतिम औषधि पर लागू होती है।
- 96. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि अंतिम औषधि की कीमत डीपीसीओ द्वारा निर्धारित होती है, तथापि एपीआई उत्पादन और बाद में औषधि उत्पादन के दो डाउनस्ट्रीम स्तरों में उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि एक प्रमुख एपीआई उत्पादक ने एपीआई पर आने वाली लागत की मात्रा संबंधी सूचना दी है, तथापि औषधि स्तर पर आगे और लागत वृद्धि की सूचना किसी हितबद्ध पक्षकार ने नहीं दी है। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के उत्तर में उठाए गए पूर्वोक्त मुद्दों संबंधी सभी अनुरोधों पर विचार किया है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

97. उठाए गए विवादों, प्राप्त जानकारी, प्रस्तुतियों और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इन निष्कर्षों में दर्ज किया गया है और डंपिंग के निर्धारण के आधार पर, और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को चोट के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि:
 - क. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर विषय देश से निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग होती है।
 - ख. विषय वस्तुओं के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच से पता चलता है कि विषय देशों से आयात की मात्रा पूर्ण रूप से और भारत में खपत के संबंध में भी बढ़ी है।
 - ग. जबकि मांग 100 आधार अंक से बढ़कर 137 आधार अंक हो गई है, घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष में 100 आधार अंकों से बढ़कर पीओआई में 1027 आधार अंक हो गई है। तथापि, घरेलू बिक्री भारत में संबद्ध वस्तु की कुल मांग का केवल 20% है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग निवल बिक्री प्राप्ति को पहुंच कीमत से काफी कम रखकर अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है।
 - घ. पीओआई सहित चोट जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम रहा है।
 - ड. पीओआई सहित चोट जांच अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता में वृद्धि हुई।
 - त. आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है।
 - थ. घरेलू उद्योग जांच की अवधि सहित पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान पहुंच कीमत से नीचे फंसा हुआ है और कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने कहा है कि पाटित आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका जो अन्यथा काफी हद तक हो गई होती।
 - द. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।
 - ध. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि अंतिम दवा की कीमत डीपीसीओ द्वारा तय की जाती है, एपीआई उत्पादन के दो डाउनस्ट्रीम चरणों और बाद में दवा उत्पादन में उत्पादन की लागत में वृद्धि हो सकती है। जबकि मुख्य एपीआई उत्पादकों में से एक ने एपीआई के लिए खर्च की गई लागत के परिमाणीकरण पर इनपुट दिए हैं, दवा के स्तर पर और लागत वृद्धि किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के प्रत्युत्तर में किए गए उपर्युक्त मुद्दों पर सभी अनुरोधों पर विचार किया है। चूंकि अनुशंसित शुल्क कम शुल्क नियम के अनुसार क्षति मार्जिन पर आधारित है, इसलिए अनुशंसित शुल्क काफी उचित है और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
 - न. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारणात्मक लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
 - प. नियमों के नियम 4(डी) और नियम 17(1)(बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के कम के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, प्रदान की गई जानकारी और इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, एंटी-डंपिंग शुल्क के बेंचमार्क/संदर्भ प्रपत्र की सिफारिश करना उचित समझा जाता है। प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश में मूलतः या वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के आयात पर दो साल का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित माल के पहुंच मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बीच

अंतर के रूप में की जाती है, बशर्ते पहुंच मूल्य से कम हो कॉलम 7 में दर्शाया गया मान। यदि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है, तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	माप की यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2932, 2933	“(4आर- सीआईएम)-1,1- डिमिथाइलेथाइल- 6-साइनोमिथाइल- 2-2-डिमिथाइल- 1,3-डायोक्सेन-4- एसिटेट जिसे एटीएस-8 के रूप में भी जाना जाता है	चीन जन.गण.	चीन पीआर सहित कोई भी देश	जियांग्सु एल्फा फार्मास्युटिकल कं. लि.	119.21	किलोग्राम	यूएसडॉलर
2	वही-	वही-	चीन जन.गण.	चीन पीआर सहित कोई भी देश	झेजियांग होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	119.21	किलोग्राम	यूएसडॉलर
3	वही-	वही-	चीन जन.गण.	चीन पीआर सहित कोई भी देश	झेजियांग लेपु फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	शून्य	-	-
4	वही-	वही-	चीन जन.गण.	चीन पीआर सहित कोई भी देश	जियांग्सु युतियान फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	119.21	किलोग्राम	यूएसडॉलर
5	वही-	वही-	चीन जन.गण.	चीन पीआर सहित कोई भी देश	क्रमांक 1 से 4 पर निर्माता के अलावा कोई अन्य	119.21	किलोग्राम	यूएसडॉलर
6	वही-	वही-	चीन पीआर के अलावा कोई भी देश	कोई	कोई	119.21	किलोग्राम	यूएसडॉलर

ड. आगे की प्रक्रिया

98. इन निष्कर्षों से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ एक अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDING

New Delhi, the 1st August, 2022

Case No. AD-OI-11/2021

Sub. : Anti-dumping investigation concerning imports of “(4R-Cis)-1, 1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2, 2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8” originating in or exported from China PR.

F. No. 06/11/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s. Arch Pharmalabs Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “Petitioner”) filed an application/petition seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “Product Under Consideration” or “PUC”) from China PR (also referred to as the “subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).
2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide notification No. 6/11/2021-DGTR dated 2nd August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of Anti-Dumping Duty (ADD), which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 2nd August, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 2nd August, 2021 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations, the domestic industry and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
- Changzhou United Chemical Co. Ltd
 - China Sinopharm International Corporation Ltd
 - Hangzhou Proserre Chemical Co. Ltd
 - High Hope International Group
 - Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co. Ltd
 - Zhejiang Medicines & Health Products
 - Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd
- g. In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response;
- Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd
 - Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd
 - Hangzhou Proserre Chemical Co., Ltd
 - Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd
 - Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd
 - Jiangsu Pfri Pharmaceutical Co., Ltd
- h. Also, apart from the exporters, China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE) also filed its comments.
- i. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- Amoli Organics Pvt. Ltd
 - Aurobindo Pharma Ltd
 - Biocon Limited
 - Dr. Reddy's Laboratories Ltd
 - Hetero Labs Ltd
 - Ind-Swift Laboratories Ltd
 - Lupin Ltd
 - Macleods Pharmaceuticals Ltd
 - Enaltec Labs Pvt Ltd
 - Sun Pharmaceutical Industries Ltd
 - Cadila Healthcare Ltd
- j. In response, none of the importers/users filed any importer's questionnaire response within the stipulated time. Dr. Reddy's Laboratories Ltd filed the importer's questionnaire response at a belated stage. The following importers/users filed their submissions:
- Amoli Organics Pvt Ltd
 - Dr. Reddy's Laboratories Ltd
- k. All the submissions as above filed are also considered and addressed to the extent found relevant as per the consistent practice of the Authority.
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/made by the various interested parties to the other parties by directing the parties to exchange such submissions via e-mail based on the list of interested parties relevant for the subject investigation made available to all relevant parties on the website of the DGTR.

- m. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S transaction-wise details of imports data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure–III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic industry.
- o. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019, April 2019 - March 2020 and the POI.
- p. Desk verification of the information provided by the applicant, responding producers and exporters from the subject country to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary modification/rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final finding.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held via video conferencing on 28th October, 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions by 8th November, 2021, followed by rejoinders, if any, by 15th November, 2021.
- r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation so far, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority, in this final finding.
- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- u. ‘***’ in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = Rs.75.22

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration and like article were defined as:

Product under consideration

3. *The product under consideration (“PUC”) is “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8”. While the chemical name of the product remains “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate”, the product is also known in trade names like ATS-8, ASC-3P, TBIN, Cyano Ketal Compound and Atorvastatin Intermediate wherein ATS-8 is the most commonly used trade name.*

4. *ATS-8 is a key intermediate for manufacture of Atorvastatin API (Active Pharmaceutical Ingredient). Atorvastatin drug formulation is widely used to treat for lowering of excess cholesterol condition in the human beings, which can otherwise lead to cardio vascular problems like heart attack and stroke, if not treated. This is a lifesaving drug finding classification under the National List of Essential Medicines (NLEM). The intermediate is manufactured in the form of bulk powder by the company and does not have any separate grades or types.*

5. The imports of the PUC have been reported under subheadings of Chapter 29 for the purpose charging of duty at the time of imports with highest imports having been reported under subheading numbers 2932 and 2933 though there have been imports under other subheadings like 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 and 2934 also as per the petition.

Like Article

6. The applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

7. The applicant has claimed that there are no known major differences in the production process employed by the applicant and the exporters from the subject countries. Therefore, for the purposes of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as "like article" to the product under consideration being imported from the subject country".

2. C.1 Submissions of the domestic industry

5. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:

- i. The product under consideration ("PUC") is "(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8". While the chemical name of the product remains "(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate". The product is also known in trade names like ATS-8, ASC-3P, TBIN, Cyano Ketal Compound and Atorvastatin Intermediate wherein ATS-8 is the most commonly used trade name.
- ii. ATS-8 is a key intermediate for manufacturing of Atorvastatin API (Active Pharmaceutical Ingredient). The subject goods as covered in the investigation have been produced and sold by the domestic industry in the period including the POI and such goods also have been getting imported into India from China PR in the same period.
- iii. The Authority may treat the subject goods produced by the applicant in India as "like article" to the product under consideration being imported from the subject country.
- iv. It has been contented by a user/importer that some imports of the PUC have been taking place due to purity issues in the subject goods produced by the petitioner. The contention has no basis. In fact, the issue has not been reproduced in writing though raised orally. The petitioner has been producing and supplying the product as per the requirements of the consumers and all such purity levels offered by the exporters have been supplied by the petitioner also. The petitioner has the technical ability to achieve the chemically possible highest level of purity. None of the responding exporters also have raised any product difference in terms of purity or other aspects.

3. C.2 Submissions by the other interested parties

6. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article:

- i. The product involved in the investigation produced and sold by the Respondent is (4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8.
- ii. There is no difference in physical/ technical/ chemical characteristics between the PUC exported to India and the PUC sold in the domestic market or exported to other countries.
- iii. There is no difference between the product produced by the respondent and the product defined by the Authority.

4. C.3 Examination by the Authority

7. The PUC in the present investigation is "(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8" originating in or exported from China PR. The product is also known in trade names like ATS-8, ASC-3P, TBIN, Cyano Ketal Compound and Atorvastatin Intermediate wherein ATS-8 is the most commonly used trade name.

8. ATS-8 is a key intermediate for manufacture of Atorvastatin API (Active Pharmaceutical Ingredient). Atorvastatin drug formulation is widely used in treatment for lowering of excess cholesterol condition in the human beings, which can otherwise lead to cardio vascular problems like heart attack and stroke, if not treated.
9. The imports of the PUC have been reported under subheadings of Chapter 29 for the purpose of charging of duty at the time of imports with highest imports having been reported under subheading numbers 2932 and 2933 though there have been imports under other subheadings like 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 and 2934 also as per the petition.
10. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:
"Like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
11. It is noted that there are no contentions raised by the responding parties on the PUC and like article.
12. After considering the information on record, the Authority holds that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

13. The submissions made by the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry & standing are as follows:
 - i. M/s. Arch Pharmalabs Limited is the sole producer of the subject goods in India. The petitioner holds 100% share in the total Indian production.
 - ii. The petitioner has not imported the subject goods from the subject country and the petitioner is also not related to any importer/s or exporter/s of the subject goods from subject country.
 - iii. The petitioner fulfils the criteria under Rule 2 (b) read with Rule 5(3) of the AD Rules to be considered as the domestic industry concerning the subject goods.

D.2. Submission of the other interested parties

14. It is noted that none of the interested parties have raised any contentions on the claims of the petitioner on their qualification as domestic industry and standing therein.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2 (b) of the AD rules defines the "domestic industry" as under:
"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"
16. It is noted that the application has been filed by M/s. Arch Pharmalabs Limited. It is also noted that the applicant is the sole producer of the subject goods in India and this claim of the applicant is not disputed by any of the responding interested parties. It is further noted that the applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. In view of the above, the Authority considers that the applicants fulfil the criteria of the domestic industry and the standing as laid down under the Indian Anti-dumping Rules. The Authority, holds the petitioner/applicant as the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5

E. ISSUES ON CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions made by the domestic industry**

17. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
 - i. The excessive confidentiality adopted by the responding parties in their responses have handicapped the domestic industry from filing any effective rebuttals to the submissions/responses by such responding parties.
 - ii. There is no indexation provided in the IQR filed by Dr Reddy's Laboratories in its appendixes concerning volume and price parameters and not providing indexation even at possible places such as on volume and average price information is a clear and blatant violation of anti-dumping rules governing confidentiality.
 - iii. The responding exporters have not disclosed the name of the parties involved in the export value chain and held the enclosures containing such details as confidential. There is no justification given for claiming such basic information as confidential. In any case, the names of parties in the export value chain cannot be confidential in any manner whatsoever and claiming the name of parties involved in the export value chain is a blatant abuse of the confidentiality rules.
 - iv. The exporters have adopted reverse indexation in their response which is not as per the format prescribed by the Authority. Such presentation of data violates the requirements as stipulated by the Authority. This is when the domestic industry has submitted the information as prescribed by the Authority.

E.2. Submissions made by other interested parties

18. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
 - i. The petitioner has not provided a broad description of the manufacturing process employed. The same has been kept confidential on a vague and bald reasoning. The information provided by the domestic industry for these parameters should be disregarded as per Rule 7 of the AD Rules.
 - ii. The petitioner has not submitted the soft format of the transaction wise import data that the Authority has relied on for the initiation of the present investigation. However, in accordance with the Hon'ble CESTAT's decision in Exotic Decor Pvt. Ltd vs. Designated Authority [Final Order No. 50689-50690/2020 dated 12.06.2020 in Anti-Dumping Appeal No. 52233 and 52239 of 2018], this data is required to be shared with all the interested parties.
 - iii. The non-confidential version of the petition does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein. The non-confidential version of the petition clearly violates the requirements specified in Rule-7 of the Rules.
 - iv. The non-confidential version of the petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Director General. Part VI costing information of the petition is not part of NCV.
 - v. Trade Notice 01/2013 dated 9th December 2013 mandates the petitioner to provide annual reports and balance sheets and the same is not provided. Since the annual accounts and balance sheets are available at MCA Portal on the payment of some fee, the same cannot be claimed as confidential as per the guidelines in trade notice.

E.3. Examination by the Authority

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

20. As required under Rule 6 (7), the Authority made available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation. Such information was circulated among the participating interested parties with directions for exchange of such evidences among the interested parties participating in the investigation to avoid physical access to the public file on account of the restrictions put in place in view of the pandemic situation.
21. The Authority notes that the information provided by the domestic industry and other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential.
22. With regard to the contention that the transaction wise import data as per DGCI&S in soft copy is not placed in the public file, the Authority notes that the consolidated data relating to volume and value of imports from all sources of imports has been shared with the interested parties. It is further noted that the Authority had authorized all the interested parties which sought authorization for obtaining DGCI&S transaction-wise data. The import data has been provided to the interested parties as per the Trade notice issued by the Directorate. This being the case no prejudice appears to have been caused to the interested parties.
23. With regard to the contention of the opposing party that the annual report of the petitioner cannot be treated as confidential as the same can be obtained from the website of the Ministry of Corporate Affairs, the Authority notes that the information available on the website of the said Ministry primarily concerns with the administration of Companies Act 2013 and the same can be obtained on payment of a fee only which shows some reasonable restriction on obtaining such information.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submission of other interested parties

24. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to various issues:
 - i. If anti-dumping duty is imposed on the subject imports, the respondents will have to purchase most of their requirement from the petitioner.
 - ii. Though the petitioner may already be supplying the PUC to the users, when the quantum of supply increases, any change in vendor of raw material involves significant changes required to be made at all levels considering the heavily regulated pharmaceutical industry.
 - iii. Any change in vendor will require following fresh vendor approval process, which takes approximately 1 year. Further, a change in vendor of raw material will also require the respondents' customers to mention the change in source in their regulatory filings. The amendment in regulatory filings may take approximately 6-7 months. Switching a vendor is extremely difficult and a time and cost intensive exercise.
 - iv. Further, the imposition of anti-dumping duty would result in a monopolistic market situation as the petitioner is claiming to be the only manufacturer of the PUC in India. This may significantly alter the present market situation where the users are able to import at competitive prices considering that there are various exporters of the PUC from the subject country.
 - v. Imports from China PR were necessary to bridge the gap between the total demand and supply by the petitioner in the domestic market.

- vi. The petitioner has not brought forth any substantive evidence to establish the conditions for initiation of the anti-dumping investigation, while the investigating authority has not carried out appropriate, enough scrutiny to the related facts. The initiation of the present investigation is totally baseless, and the investigating authority ought to terminate the current investigation.
- vii. The petitioner is suffering injury since 2009-10. If the petitioner had suffered such severe injury from the imports from the subject country, then why they had not come before the Authority at that time. It appears that there were some other reasons which caused injury to the domestic industry that further led it to become a sick unit which have not been provided in the petition.
- viii. The Authority is requested to examine the report submitted before BIFR in which the reasons for company becoming sick are clearly provided.

F.2. Submissions made by the domestic industry

25. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. It has been elaborated in the petition that the petitioner faced shutdown during 2013-2016 period and the petitioner recommenced its production from FY2016-17 based on a financial Restructuring Agreement (Rehabilitation/Revival Package) reached with M/s JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd. The accrual of debt was primarily the result of adverse business environment created by unfairly priced imports and its cascading effects.
- ii. It is evident in the letter addressed to BIFR dated 27.1.2016 that *the operations of the Company have been adversely affected from the financial year commencing from 1st April, 2013 due to lower pricing margins as a result of large-scale dumping from China PR accompanied with unfavorable Government policies for the bulk drug industry*. Thus, injurious dumping has been a major cause of losses in the past as well.
- iii. Also, the BIFR order referring the company under SICA, 1985 recorded the statement of the company in reply to a question from the Special Bench about the cause of the accumulated losses of the Company after its net worth had turned positive in 2004. The Counsel of the Company stated that *the company's profits dipped due to paucity of working capital, which were further exacerbated by massive dumping of Drugs & Pharma products by China in Indian and international markets*.
- iv. JMFARC invested in the petitioner for long time realizing its potentials which has helped the petitioner to recommence its production. Thus, any apprehensions on the continuity of the petitioner as a reliable producer of the subject goods based on its past issues have no basis at this juncture.
- v. The petitioner has been in operation for the past four years after the restructuring which itself shows the revival was a credible one and the debt issues as such is behind the petitioner now.
- vi. Having resurrected from its past issues, the petitioner is only vulnerable to the unabated dumped and injurious imports of the subject goods from China PR and anti-dumping duties to arrest the same will help the petitioner to operate prudently in the time to come.
- vii. The performance during the past four years after the revival package clearly underscores the credibility of the revival package and it may be noted that the benefit of the revival package can only be fully accomplished by the petitioner once anti-dumping measures are put in place to stop dumped and injurious imports of ATS-8 from China PR and we pray for such measures at the earliest.
- viii. The petitioner still has about 50% capacity unutilized and the demand supply gap cited is not any ground to deny ADD in the present matter. The contentions have no legal or factual basis when the domestic industry is sitting on unutilized capacity.
- ix. It is a settled jurisprudence that the demand-supply gap cannot justify dumped imports and the ruling of the Hon'ble CESTAT in DSM Idemitsu Ltd Vs DA matter is applicable in this matter also. The present case is not about demand supply gap, but about the inability of the Indian producer to utilize its capacity to any prudent level.
- x. Though the present capacity of the domestic industry which is *** MT is not sufficient to meet the entire Indian demand as found during the POI which is *** MT, the domestic industry can meet close to 50-60% of such demand but the fact of the matter is that the capacity of the domestic industry was underutilized to the tune of about 40-50% during the POI. It is also submitted that the domestic industry has plans to increase the capacity further to *** MT by March 2022 and the domestic industry

will be able to meet more than 80-90% of the demand thereafter with the increased capacity. The plans to increase the capacity will all be derailed if the dumping is continued unabated without any ADD in place

- xi. The IQR filed by Dr. Reddy's Laboratories Limited show that the company filed the IQR on 20.10.2021 which is much after the deadline to submit the information set by the Authority. The delay is totally unexplained and the response is rejectable.

7. **F.3. Examination by the Authority**

26. The Authority has considered the views of the interested parties, as follows:

- i. With regard to the contention that if anti-dumping duty is imposed on the subject imports, the respondents will have to purchase most of their requirements from the petitioner warranting significant changes in the vendor which involves significant process, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The purpose of imposition of an anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- ii. With reference to the contention of demand-supply gap, it is noted from the facts of the present case that the demand for the product during the POI was *** MT against which the production of the domestic industry was *** MT against a capacity of *** MT. Thus, the domestic industry has the capacity to meet almost 40-50% of the Indian demand. Though the production by the petitioner was not sufficient to meet the reported Indian demand during the POI, which could have been due to dumped imports from the subject country, however, a gap in demand and supply cannot be a reason for depriving the domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury.
- iii. With regard to the contention that ADD will lead to monopoly of the petitioner and any such measures shall be against the public interest, it is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by any anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- iv. With regard to the contention that the petitioner has not brought forth any substantive evidence to establish the conditions for initiation of the anti-dumping investigation, it is noted that the case was initiated after satisfying those sufficient evidences as required under the rules were available to justify the initiation.
- v. With regard to the contention that Dr. Reddy's Laboratories Limited filed the IQR at a belated stage, the Authority notes that Dr. Reddy's Laboratories Limited have not filed the IQR within the stipulated time. However, the submissions of the said party are proposed to be considered and addressed to the extent found relevant in this investigation.
- vi. With regard to the contention that the petitioner is suffering injury since 2009-10 and the Authority must examine the cause of such injury from the report submitted before BIFR in which the reasons for company becoming sick must have been provided, the Authority notes that the BIFR report has taken cognizance of various causes for the financial condition of the company including dumping of subject goods from the subject country being claimed as one of them. The injury period of present investigation is 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI and the scope of the present investigation covers developments during this period alone.

G. **MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

8. **G.1. Submissions made by the domestic industry**

27. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the determination of normal value, export price and dumping margin;

- i. The petition shows significant dumping taking place in the import of the subject goods from China PR and the dumping margin as per the petition is in the range of 40-50% which is above the thresholds required under the rule and also very significant.
- ii. China PR should be treated as a non-market economy country and the normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and (3) of Annexure I of the Rules. In terms of Para8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. None of the responding producers/exporters from China PR have rebutted the NME presumption by filing the applicable Questionnaire. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
- iii. The petitioner has estimated normal value for the subject country on the basis of cost of production in India, duly adjusted, as there is no reasonable information available to determine the normal value of the product based on the price in a market economy third country or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India. The product is primarily produced in India and China PR and there are no imports into India from any other countries.
- iv. Dumping is apparently adopted as a strategy to decimate the Indian production base for the PUC and it should be noted that the import price from China PR have been much lower than the cost of production, albeit adjusted cost of production of the domestic industry, causing serious injuries to the domestic industry.

9. **G.2. Submission of other interested parties**

28. The following submissions have been made by the other interested parties concerning the determination of normal value, export price and dumping margin;
 - i. In accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th Dec, 2016. Such practice is bound to expire from then on.
 - ii. Exporters are surprised to note that the Director General has issued a separate questionnaire to exporters from China PR seeking voluminous information from exporters from China PR with regard to claims of Market Economy status. China PR had been treated as a Non-Market Economy country by India in the past.
 - iii. Section 15 (a) (ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization expired on December 11, 2016. After that date, India no longer has a legal basis under the agreements of the World Trade Organization to calculate normal value in anti-dumping investigation of Chinese products using the non-market economy methodology.
 - iv. The Authority may grant "market economy status" to China PR based on the development of market economy of China; conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of the Anti-Dumping Agreement; and at the very least, apply the data on costs and prices provided by the Company in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data in this instigation.
 - v. Dumping margin should be determined based on the information provided by the producers/exporters from China PR.
 - vi. The applicant did not provide any evidence for the deductions made under the categories of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission and bank charges.
 - vii. The petitioner has claimed adjustment of non-refundable VAT without enclosing any evidence that VAT paid by Chinese exporters to the Government is non-refundable. The Authority should seek evidence from the petitioner and the participating Chinese exporters on the same.
 - viii. The petitioner has submitted the updated import data on 23.09.2021. The Authority is requested to calculate the export price by considering the actual import data submitted by the petitioner.

10. **G.3. Examination by the Authority**

11. **Normal value**

29. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

30. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have filed the response in the prescribed exporter questionnaire responses:

- i. Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd
- ii. Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd
- iii. Hangzhou Proserre Chemical Co., Ltd
- iv. Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd
- v. Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd
- vi. Jiangsu Pfri Pharmaceutical Co., Ltd

Market Economy Status for Chinese Producers

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) *"In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:*

(i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable,*

the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
32. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
33. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.
34. With regard to the submission of the interested parties that adjustments from the export price must be based on evidences and also import as per DGCI&S for the complete POI must be considered, the Authority note that the adjustments are allowed after due examination of the evidences presented and also import data as collected from the DGCI&S for the entire period of POI alone have been used.

Normal Value for all producers in China PR

35. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information as noted above, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:
- In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*
36. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I

37. The Authority notes that normal value could not be determined on the basis of prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, as the relevant information has neither been made available by the applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. There are also no imports of the subject goods from other countries into India and it has been submitted that the product is primarily produced in India and China PR only. Thus, the normal value can only be determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
38. The Authority has, thus, constructed the normal value based on the optimized cost of production, considering prices of major raw materials and other costs paid in India, as per facts available. Further, reasonable profit has been added to the cost of production for the purpose of determination of normal value. The normal value has been determined for all producers and exporters from China PR, and are mentioned in the dumping margin table.

Determination of Export Price for cooperating producers and exporters

a) M/s Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd., China PR-and M/s Jiangsu Pfri Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

39. Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd., has reported export of the *** MT subject goods to India during the POI, out of which *** MT of subject goods has been exported to India through a related trader namely, Jiangsu Pfri Pharmaceutical Co., Ltd., China PR, who has filed its exporter questionnaire response with the Authority. It is further noted that Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd., has also exported *** MT of subject goods to India through two unrelated traders namely, China Sinopharm International Corporation, and Synchem International Co., Ltd. and these two traders have not filed their exporters questionnaire response with the Authority, hence the quantity exported to India by these two traders have not been considered in the final determination.
40. Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd., has claimed adjustments on account of Air Freight, Air/marine insurance, inland freight, port charge, ocean freight, commission, bank charges and credit cost. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

b. Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

41. Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. has reported export of the subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to the customers in India. The producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India of invoice value *** US\$ during the POI. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, inland transportation insurance and credit cost. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin table below.

c) M/s Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd., China PR and M/s Hangzhou Proserre Chemical Co., Ltd., China PR

42. Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd., has reported export of the *** MT subject goods to India during the POI, out of which *** MT of subject goods has been exported to India through an unrelated trader namely, Hangzhou Proserre Chemical Co., Ltd., China PR, who has filed its exporters questionnaire response with the Authority. Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean Freight, insurance, inland transportation, inland insurance and credit cost. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin table below.

d) Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

43. Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd., has reported export of the subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to customers in India. The producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India of invoice value *** US\$ during the POI. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin table below.

Determination of Normal Value and Export Price for all non-cooperating Producers and Exporters in China PR

44. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been proposed as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

45. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been proposed as follows:

Dumping Margin Table

S.No	Producer	Normal Value US\$/ MT	Net Export Price US\$/ MT	Dumping Margin US\$/ MT	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
1	Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
2	Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
3	Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
4	Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
5	Any other producer	***	***	***	***	20-30

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the domestic industry

46. The following submissions have been made by the domestic industry:
- Information on injury parameters shows the fact that the domestic industry has suffered material injury as envisaged in the AD Rules read with Annexure II.
 - Dumped imports have increased in absolute terms and have been the cause of volume injury suffered by the domestic industry.
 - Increase in import volume was the result of a sharp reduction in the landed price of imports from China PR.
 - As a result of dumped imports, the domestic industry could never utilize its capacity to any reasonable level and as a result, more than 50% of its capacity remained idle and unutilized during the POI and the injury period. This is when the product registered consistent increase in demand.
 - The sharp increase in imports between the POI and immediate previous year has resulted in significant loss of market share to the domestic industry. While the market share of the domestic industry declined to 765 indexed points in the POI from a 996 level in the immediate previous year, market share of the dumped imports increased from 75 indexed points to 82 points in the POI.
 - The exporters gained higher market share in the POI by reducing the price of the product further and the loss of market share on account of such targeted actions have crippled the volume growth of the domestic industry demonstrating volume injury.

- vii. Though the volume parameters such as capacity utilization, production, sales etc. improved over the base year, what is notable is that the actual volume growth would have been even higher and prudent had there been no dumping.
- viii. The volume injury on account of dumped imports is reflected in the idle and underutilized capacity situation, loss of market share and underperformance in the volume parameters. The domestic industry had the potential to produce and sell more.
- ix. The price related injury parameters show that the triggering point of such price injury have been the landed price of the dumped imports which was lower than the cost of production and also fair selling price (NIP) of the domestic industry. The domestic industry was forced to sell at a price lower than the landed price of imports which was lower than its cost and have been incurring losses during the POI.
- x. It is a settled law as per the order of the Hon'ble CESTAT in the Nippon Zeon Vs Designated Authority that injury cannot be decided by assuming ideal conditions. But has to be on prevailing conditions. Though giving reasonable adjustments. Notwithstanding the said position of law, the petitioner presented its cost by making reasonable adjustments for certain interest items and it is seen that the landed price of dumped imports has still been lower than such adjusted cost of production.
- xi. The domestic industry could not realize any reasonable ROCE in the POI. The losses and unremunerative price of the domestic industry is the direct fall out of the dumped imports.
- xii. There is no requirement under the Rule or as per the practice of the Authority that price undercutting has to be positive to show price injury. Annexure II to the rule says that the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- xiii. The domestic industry could not increase its prices on account of lower landed price of dumped imports and such landed price prevented price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Price suppression and also depression effect as the domestic industry was selling at unremunerative prices is very evident in this matter.
- xiv. The cost of production declined during the POI over the immediate previous year though increased slightly over the base year. However, the selling price remained almost same during the POI in comparison to the immediate previous year.
- xv. The growth of the domestic industry have been negative in all core parameters and the negative growth during the POI was the result of increase in dumped imports during the POI coupled with a sharp decline in landed price.
- xvi. The cause of injury as claimed in the petition by the domestic industry is dumped imports alone. The petition fully meets the causality requirements as per the rule and also as interpreted by the WTO Appellate Body in the US-Hot rolled steel from Japan ADD matter.
- xvii. As demonstrated, the volume and landed price of the dumped imports has created consequential adverse effects on the volume and price performance of the domestic industry and such direct consequences of the dumped imports demonstrates causal link in the present matter.
- xviii. As a consequence of increase in the dumped imports, the domestic industry lost market share during the POI to dumped imports and also have been forced to underutilize its capacity in the entire injury period. Since there are no third country imports or competition from other producers in the country, it can be fairly noted that the volume underperformance and injury suffered by the domestic industry is clearly on account of dumped imports.
- xix. The petitioner did not attribute injury on account of any other factors but to imports. The claim that cause of injury is high interest and depreciation has no meaning.
- xx. Profit before interest, depreciation and tax also has been negative during the POI. Such negative situation shows that the claims of interest and depreciation as the cause of injury has no meaning. It is not shown by the other parties that dumped imports is not the cause of injury to the domestic industry.

- xxi. The available data from the response of the responding exporters shows that major exporters reduced the price significantly in the POI over the immediate previous year to increase their exports to India which would not have been possible without reducing the prices.
- xxii. Apart from a situation of current injury, the petitioner faces severe threat of aggravated level of dumping and consequent injury in the future as well and ADD at the earliest may be recommended keeping in view such further threat of injury.
- xxiii. The parties here have ignored the fact that there was a fall in the market share of the domestic industry in the POI viz. the immediate previous year and the capacity utilization of the domestic industry was not even 50% even by the POI in a growing demand situation which clearly show volume effects on account of dumped imports. There were no other factors which created challenges to the volume growth.
- xxiv. The domestic industry suffered injury on both volume and price fronts. The market share of the domestic industry declined significantly in the POI and capacity utilization was below par. The domestic industry suffered financial losses and the ROCE was negative in the POI and the injury period.
- xxv. The contention that losses are on account of interest and depreciation also has no meaning as the domestic industry suffered PBTID (Profit before tax, interest and depreciation) losses during the POI. The plans to increase capacity is a futuristic decision taken based on the growing and robust demand for the product and the execution will depend upon on the conducive environment for the product and such conducive situation can be put in place only by levy of ADD.
- xxvi. Job work in terms of purification of ATS-8, which had unwanted isomers, was done by the petitioner for a few unrelated parties wherein the said ATS-8 is understood to have been imported by the said parties. Details of how such job work transactions were carried out are a part of the financial statement of the petitioner.

H.2. Submissions made by other interested parties

47. The submissions made by the other interested parties have been as follows:

- i. Information provided in the petition does not support the claim that the domestic industry is suffering material injury. The increase in the volume of the subject imports must not be examined in isolation but in the context of the demand for the PUC.
- ii. The total demand of the PUC increased by 37 indexed points from the base year to the POI, whereas increase in imports in the POI as compared to base year is only 12 indexed points.
- iii. The domestic industry is able to sell whatever it has produced (based on the sales quantity and production quantity) and it is only in the period of investigation that the domestic industry has shown inventory for the first time, which indicates that the domestic industry is not doing enough production to meet the market demand.
- iv. There is an increase in the market share of domestic industry and a consequent reduction in the market share of imports from the subject country, thereby indicating that there is a significant increase in the sales by the domestic industry. Further, there is an increase in sale of domestic industry by 923 indexed points in the POI compared to the base period.
- v. Even though demand of the PUC declined in 2019-20 to 101 indexed points in comparison 113 indexed points in 2018-19, the domestic industry's production increased significantly from 275 indexed points in 2018-19 to 996 indexed points in 2019-20. Market share of the domestic industry increased from 243 indexed points to 986 indexed points in the same period. Thus, even in declining demand, the domestic industry aggressively captured market share.
- vi. When demand increased in the POI to 137 indexed points, the domestic industry's domestic sales further increased to 1023 indexed points. Although the subject imports also increased during the POI but the imports only followed the trend of increase in demand in India and the petitioner's capability to cater to the same.
- vii. With regard to the increase in the volume of subject imports in relation to the production, the domestic industry has been able to scale up its capacity and production during the POI. Therefore, there can be no volume effect in relation to production.

- viii. With regard to the increase in the volume of subject imports in relation to consumption, in spite of an increase in absolute terms and increase in demand in India, the volume of subject imports in relation to consumption has declined after the base year.
- ix. Price under cutting has been negative during the entire injury period. This is despite the fact that the domestic industry has increased the price by 30 indexed points in the POI compared to the base period. Therefore, there is no price effect.
- x. The landed prices of imports had continuously and significantly increased throughout the injury period, except for the reduction in the POI.
- xi. There is neither any price suppression nor any price depression in the facts of the present case. The domestic prices have moved independent of the landed prices.
- xii. The installed capacity has increased by more than 100% in 2019-20. As stated, the said increase is not due to any new capital expenditure, but due to transfer of existing assets to the PUC. Further, the capacity is expected to increase by 2022. If the domestic industry was indeed being injured due to the subject imports, it would not have been able to transfer existing assets or commission new capacity in the future.
- xiii. The petitioner have themselves admitted that sales volumes and values have increased continuously and significantly throughout the injury period. Therefore, there is no injury in this regard.
- xiv. The petitioner have themselves submitted that the number of employees and their productivity have increased. Also, it is admitted that there is no inventory build-up till the POI.
- xv. Prior to the injury period, the domestic industry was suffering major financial setbacks which affected their performance. Therefore, during the injury period, though the petitioner was reviving, they were suffering heavy losses. A closer look on the reasons for such losses would make it clear that the losses were due to the finance costs and depreciation which increased exponentially during the injury period.
- xvi. From the base year, the finance costs and depreciation increased by 40 times and 20 times respectively. This has led to the decrease in overall profitability of the petitioner.
- xvii. The ROCE has reduced exponentially during the POI only because of the reduction in Average Capital Employed and not due to the increase in losses.
- xviii. Out of the mandatory parameters prescribed in para (iv) of Annexure II, almost all the parameters have shown improvement in the POI as compared to the base year. Decision of WTO panel in Thailand – H-Beams (WT/DS/122/R) is relevant here.
- xix. There is absence of causal link between subject imports and petitioner's economic performance. Injury, if any, is attributable to factors other than subject imports.
- xx. Factors such as no correlation between volume of subject imports and petitioner's economic performance, there is a negative price undercutting and absence of price suppression and depression, the petitioner has earned positive operating profits during 2018-19 and 2019-20 as per the annual reports, and the overall losses are only due to the high finance costs and depreciation of the domestic industry shows absence of causal link.
- xxi. In the final findings of the safeguard investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series, it was explicitly held that abnormally high depreciation and finance charges broke the causal link.
- xxii. The analysis of the balance sheets of the petitioner for the year 2018-19 and 2019-20 shows that there seems to be no increase in equity share capital and long-term borrowings. However, in the petition, heavy increase in equity and borrowings could be seen. The Authority is requested to verify as to how the funds are allocated to the PUC as per the petition when there is no significant change in the same as per the financial statements of the petitioner.
- xxiii. Imports from China PR do not cause any injury to the domestic industry during the injury period and the period of investigation. Demand of the subject goods has increased from 100 (2016-17) to 137 during the POI. Whereas, imports from the subject country have increased only by 12%, from 100 (2016-17) to 112 during the POI, even less than the increase in demand.

- xxiv. Imports in relation to production and demand have shown sharp decline during the POI as compared to the base year 2016-17. Thus, there is no volume injury to the domestic industry from the imports from China PR.
- xxv. Negative price undercutting shows the fact that the domestic industry is selling their goods at a price lower than the import price. In case the domestic industry is facing losses due to less cost, it may increase the prices of the subject goods. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to the imports from the subject country.
- xxvi. In the recently concluded case of Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR, price undercutting was considered as an important parameter and the Authority recommended dis-continuance of the ADD levied on the PUC.
- xxvii. It seems that the petitioner has manipulated the data to deliberately invent injury. There is no correlation between the data provided by the petitioner as with the manifold increase in sales volume and selling price; the profitability of the company shall improve accordingly. However, it has shown sharp decline which is suspicious. The Authority shall critically examine the same.
- xxviii. The interest and finance cost has increased abnormally from 100 during the base year 2016-17 to 4145 during the POI. Such irregular trend may be seen in the increase in depreciation also. The Authority is requested to critically examine the same.
- xxix. Abnormal trend of ROCE is seen. The Authority is requested to critically examine the same.
- xxx. The company was shut down in the past as a sick unit and reason for the same played a very important role in the deterioration of the performance of the domestic industry which is attributed to alleged dumping of subject goods.

H.3. Examination by the Authority

- 48. The Authority has taken note of the various submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 49. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 50. It is also noted that the contentions of the opposing parties as captured herein above are on the claims of injury by the domestic industry and such contentions are addressed ipso facto here under while examining the injury parameters and in view of the same contention on injury is not being addressed separately for the sake of brevity.

i. Volume Effect of Dumped Imports on the domestic industry

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

- 51. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and the imports from all sources. The demand so assessed has increased during the injury period.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Imports from China PR	MT	397	431	303	446
Trend	Indexed	100	109	76	112
Total imports from other countries	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total imports into the country	MT	397	431	303	446
Domestic sales of the petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	273	1000	1027
Domestic sales of other producers	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	101	137

52. As can be seen from the above table, demand for the subject goods in India during the POI has increased over the base year and also over the immediate previous year.

b. Import volume from the subject country

53. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Imports from China PR (subject country)	MT	397	431	303	446
Share of subject country in total imports	%	100	100	100	100
Share of other countries in total imports	%	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	%	100	100	100	100

54. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject country has increased in absolute terms from 397 MT in the base year to 446 MT in the POI.

c. Subject country imports in relative terms

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Imports from the subject country	MT	397	431	303	446
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	101	137
Production of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	273	1000	1045
Import from subject country relative to					
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	75	82
Production of the domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	40	8	11

55. It is noted that the imports from the subject country relative to Indian consumption and production of the domestic industry declined between the base year and the POI. The same, however, increased in the POI when compared to the previous year.

ii. Price effect of the imports on the domestic industry

56. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
57. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject country.

a) Price Undercutting

58. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject country with the net sales realisation of the domestic industry in India.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Net sales realization	Rs./kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	130	130
Landed price	Rs./kg	6,116	7,841	9,520	8,801
Trend	Indexed	100	128	156	144
Price Undercutting	Rs./kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	Negative	Negative	Negative	Negative

59. It is noted from the aforesaid table that the imports from the subject country have been entering Indian market at a price above the net sales realization of the domestic industry, resulting in negative price undercutting. The Authority also notes that the landed price has been higher than the net sales realization throughout the injury period including the POI.

b) Price Suppression/Depression

60. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress the prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Cost of Sales	Rs. /Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	124	114	115
Selling Price	Rs. /Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	123	130	130
Landed Price	Rs. /Kg	6,116	7,841	9,520	8,801
	<i>Indexed</i>	100	128	156	144

61. It is observed that the cost of sales increased from 100 basis points to 115 basis points from 2017-18 to the POI while the selling price increased from 100 basis points to 130 basis points during the same period whereas the landed price increased from 100 to 143 basis points during this period. It is also noted that the landed price has remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period.

iii. Economic Parameters of the domestic industry

62. Annexure-II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

63. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	223	223
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	273	1000	1045
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	278	456	478
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	273	1000	1027

64. It is noted that the capacity, production, capacity utilization and domestic sales increased over the injury period.

b) Market Share in Demand

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Imports from China PR	MT	397	431	303	446
Total imports from other countries	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total imports into the country	MT	397	431	303	446
Domestic sales of the petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	273	1000	1027
Domestic sales of other producers	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	101	137
Share in Indian demand relative to					
Imports from China PR	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	75	82
Total imports from other countries	%	Nil	Nil	Nil	Nil

Total imports into the country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95.9	75.3	82
Domestic sales of the petitioner	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	233	900	700
Domestic sales of other producers	%	Nil	Nil	Nil	Nil

65. The Authority notes that the market share of the subject goods declined between the base year and 2019-20 but increased in the POI when compared with the previous year.

c) Profitability, return on investment and cash profits

66. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Cost of Sales	Indexed	100	124	114	115
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Selling Price	Indexed	100	123	130	130
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Profit/Loss	Indexed	-100	-126	-91	-94
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Profit/Loss	Indexed	-100	-347	-907	-960
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Cash Profit	Indexed	-100	-351	-913	-929
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
PBIT	Indexed	-100	-186	-389	-457
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Capital employed	Indexed	100	112	248	253
ROCE	%	***	***	***	***
ROCE	Indexed	-100	-165	-157	-186

67. It is noted that the profitability per MT of the domestic industry and return on capital employed, cash profit was negative in the POI.

d) Employment, productivity and wages

68. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	148	151
Wages	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	156	226	730
Productivity per employee	MT/Person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	240	672	692

69. It is seen that employment levels, wages, and productivity of the domestic industry increased during the injury period. The Authority notes that there has been more than 300% increase in the wages of POI as compared to the previous year without any major change in the number of employees. The petitioner has provided no adequate justification of the same.

e) Magnitude of Dumping Margin

70. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

f) Inventories

71. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Inventory	MT	-	-	-	***
Trend	<i>Indexed</i>	-	-	-	100

72. It is noted that there was no inventory buildup with the domestic industry between base year and 2019-20. However, some inventory buildup took place in the POI.

g) Growth

73. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to the volume parameters like production, capacity utilization and sales volume have been positive but market share and price parameters such as profits and return on capital employed have been negative during the POI as can be seen from the table below;

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (POI)
Production	%	-	172.73	266.67	4.55
Sales Volume Domestic	%	-	172.73	266.67	2.73
Capacity Utilization	%	-	177.78	64.00	4.88
Market Share	%	-	142.98	305.94	-22.44
Selling Price Per KG	%	-	22.95	5.76	-0.14
Cost of Sales Per KG	%	-	241.29	233.98	3.64
Return on Capital Employed	%	-	-65.46	5.33	-18.84
Profit per Unit	%	-	-26.28	27.91	-3.10
PBIT Per Unit	%	-	-85.82	-109.09	-17.72
Productivity per Employee	%	-	166.67	168.75	4.65

h) Ability to raise capital investments

74. The Authority notes that the domestic industry has made capital investments to set up the plant to produce the subject goods and the domestic industry faced shut down prior to the injury period. The domestic industry has recommenced production with fresh capital infusion as a part of restructuring during the injury period.

i) Magnitude of Injury Margin/Price Underselling

75. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. The Authority has excluded the job wok related expenses in computation of cost of production for the PUC. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed for recovery of interest, corporate tax and profit as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

76. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
77. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority.

Injury Margin

Country	Producer/Exporter	NIP (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
China PR	Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
China PR	Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
China PR	Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
China PR	Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
China PR	Any other	***	***	***	***	10-20

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

78. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

(i) Volume and price of imports from third countries

79. There were no imports of subject goods taking place from any country other than the subject country.

(ii) Export Performance

80. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis.

(iii) Contraction in demand/Changes in pattern of consumption

81. It is noted that the demand of the subject goods has increased over the injury period.

(iv) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

82. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(v) Developments in technology

83. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology.

(vi) **Changes in pattern of consumption**

84. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable. No evidence has been provided by any of the interested parties to demonstrate change in pattern of consumption.

(vii) **Performance of the domestic industry with respect to other products**

85. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performances concerning the subject goods. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(viii) **Productivity of the domestic industry**

86. Productivity per employee increased by the POI.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

87. The Authority issued disclosure statement containing the essential facts in this investigation to the interested parties on 18.07.2022 and the interested parties were allowed time up to 22.07.2022 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered and examined, to the extent found relevant, as below:

J.1 Submissions by the other interested parties

88. The submissions made by the other interested parties are as under:

- i. The subject goods assume critical importance for India and imposing anti-dumping duty on the same would be detrimental to public interest.
- ii. The increase in the imports of the subject goods relative to the Indian consumption is minor and does not justify imposition of the anti-dumping duty.
- iii. The price undercutting has been negative throughout the injury period, because the landed value of the subject goods remained above the net sales realization of the domestic industry throughout this period. The Authority is requested to examine why the domestic industry was not able to increase its prices because it seems to be a case of self-inflicted injury.
- iv. A look at the financial statements of the domestic industry shows that they have been in operating profits since 2018-19 but incurred losses after adjustment of very high interest cost, and depreciation and amortization cost.
- v. Further, from the statement of cash flows of the petitioner during the injury period, it is clear that the petitioner has been earning positive operating cash flows.
- vi. It is only due to the high interest costs that the petitioner is suffering injury. Further, the petitioner have themselves not considered the finance costs as part of the operating costs in the financial statements filed with the MCA. Therefore, the Authority should adopt the same approach and disregard interest while analysing the profitability of the PUC.
- vii. The profits have drastically increased due to some inclusion of exceptional income. Further, there are some exceptional expenses included in the other expenses. The petitioner is earning profits even after removing such exceptional items. This is explained from the table below:
- viii. From the above, it is clear that the petitioner has actually earned profits during the POI, and it is not merely due to inclusion of the exceptional income. Therefore, there is no causal link between the subject imports and the petitioner's performance.
- ix. The constructed normal value and non-injurious price of the domestic industry should be determined after adjusting for abnormal interest cost, depreciation and amortisation cost, and wage cost. Without making these adjustments, the dumping margin and injury margin would be very high and unjust.
- x. The cost of PUC constitutes about 30-35% of the total cost of manufacturing Atorvastatin API bulk drug. Further, the cost of PUC constitutes 18-23% of the selling price of Atorvastatin API bulk drug. Dr. Reddy's has provided evidence on record to support the above figures. Further, in our estimate, cost of PUC constitutes about 15-20% of the cost of Atorvastatin formulation/tablet. Thus, an anti-

dumping duty of 20-30% will have a significant impact on the profitability of Dr. Reddy's and Amoli. Further, any change in the vendor of the raw material involves significant changes required to be made at all levels considering the heavily regulated pharmaceutical industry.

- xi. The price of the subject goods is fairly stable. To balance the interest of the domestic industry and users, in case the Authority decides to recommend imposition of anti-dumping duty, the Authority may kindly recommend reference price form of duty.
- xii. The Authority should not use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case. The Authority should calculate the dumping margin based on Hongyuan Pharmaceutical's own data of domestic sales or cost.
- xiii. The data used to calculate normal value and NIP is over-protected, due to which Hongyuan Pharmaceutical could not provide meaningful and effective comments.
- xiv. The economic parameters depict that there is no injury to the domestic industry and if any, that cannot be attributed to the imports of subject goods from China PR. It seems that data is manipulated by the petitioner to purposely create the injury. In the recently concluded case of Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR, economic parameters were considered as an important parameter and the authority recommended dis-continuance of the ADD levied on the PUC
- xv. The 22% ROCE used in calculating the NIP is not appropriate and should be modified.

J.2 Submissions by the domestic industry

89. The submissions made by the domestic industry are as under:

- a) NIP determined for the domestic industry is very low and needs reconsideration by proper appreciation of facts. The low injury margin on account of low NIP will benefit the exporters who are engaged in dumping
- b) Low NIP may defeat the whole purpose of any ADD to counteract dumping causing injury to the domestic industry. The following concerns on NIP determination must be please addressed in the final finding;
 - i. The Authority has disallowed some of the main expenses claimed by the domestic industry which tabulated in the comments. Clarification sought vide e-mail dated 21st July, 2022 in this regard is yet to be received and we request such clarification prior to the issuance of finding to avoid miscarriage of justice. Comments are filed on time without such clarification to avoid any delay in investigation.
 - ii. Basis of allocation of salary and wages in the determination of NIP in the disclosure needs to be changed to make it reasonable and logical. Instead of production volume, machine hours should be considered as the basis of apportionment in the peculiar facts of the present case.
 - iii. The company has undertaken some job work of purifying ATS-8 by activating it with Mother Liquor and the process has taken only 0.19% of total Machine hours. However, if such job work is considered as production activity, then such job work makes for 58.48% of the total production volume leading to job work absorbing major share of salary and wages at the time of apportioning the cost.
 - iv. Para VI of Annexure-III to the Rules requires that the basis of apportionment must be reasonable and scientific. Thereafter, an indicative basis is stipulated and a hierarchy is visible in the stipulation commencing from machine hours and it goes on. Thus, machine hours as a basis of apportionment of salary and wages as being requested by the domestic industry has clear backings in the Rule and the facts of the present case shows that the method is fully reasonable and scientific and the details of machine hours is also available.
 - v. Annexure III to the rules provides for a reasonable return on capital employed while determining NIP for the domestic industry. But in the facts of present case, calculation shows negative return considered which is not the intended purpose of the rule.
 - vi. As per Para VIII of Annexure III read with Para IX, interest is allowed as an item of cost of sales. Hence, interest cost after reasonableness test based on Para-IX has to be allowed as cost

- of sales. The stipulation in para VIII that the balance amount of return is to be allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price clearly talks about balance amount only in positive count/sense since a negative amount cannot take care of pre-tax profit.
- vii. It is understood that the Authority allows minimum 5% return in case the return calculated is actually less than 5% in the computation of NIP and such methods to ensure a reasonable return must be allowed in case of a negative scenario also.
 - viii. In fact, domestic industry did not get any opportunity to clarify the basis of allocation earlier, as the inappropriateness of the basis of apportionment has become evident only upon receipt of the subject Disclosure statement. However, it is felt that the comments on Disclosure statement stage is not any belated stage to clarify the basis of allocation. Also, the DI had submitted all information relevant to determine the basis of allocation including details of machine hours etc.
- c) The Authority may confirm its proposals on PUC and like article in the Final Finding.
 - d) The Authority may confirm its proposals on the aspect of standing and the domestic industry in the final finding.
 - e) The Authority may relook at the normal value determined based on our comments on cost relied upon for determination of NIP. It is felt that the dumping margin in case of Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd also shall be very significant.
 - f) The domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject country and a causal link between dumping and injury is also evident.
 - g) The domestic industry has suffered severe financial losses as a result of price effects created by the landed price of dumped imports and even the volume parameters have been at below par levels on account of huge presence of dumped imports in the Indian market holding substantial part of the market share.
 - h) The case clearly warrants anti-dumping duties to correct the effect of dumping.
 - i) It is notable that even though the price undercutting was negative in the injury period, what is really notable is that the landed price has remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period. Clearly, the dumped imports prevented price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. Such landed price even below the cost of the domestic industry is the cause of injury to the domestic industry.
 - j) The domestic industry is really concerned that the injury margin is negative in case of Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd and the margin is very low for the other two responding exporters. The cause of such low margin is clearly the low NIP determined by the Authority and the imports from all such exporters have been reaching India at very low prices causing severe price pressure on the domestic industry. The Authority may revisit the injury margin calculations based on our comments on the NIP computation.
 - k) It is reiterated that as per the estimates of the petitioner, ATS-8 may account for a meagre 1.5% to 2% cost of Atorvastatin Drug and any ADD will have only very minuscule effect on the end drug as the cost of intermediate in such drug as such is very small. The general public will not be impacted on account of ADD in any significant manner. At the same time ADD will ensure continued existence of the domestic industry which shall ultimately be in the benefit of users in India.

J.3. Examination by the Authority

- 90. The Authority notes that the post-disclosure comments/submissions made by the domestic industry and the other interested parties are mostly reiterations of their earlier submissions, which have already been examined adequately addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The Authority has examined the submissions herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere are examined as under:
 - i. The Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of information furnished by the domestic industry, principles laid down in Annexure III of Anti-Dumping Rules and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

- ii. The Authority notes the contentions of the interested parties regarding impact of imposition of anti-dumping duties on their profitability. In this regard, the Authority re-iterates that though the cost of the PUC in the manufacturing of Atorvastatin API bulk drug has been provided, the further cost increase at the drug stage has not been provided by any interested party. In the absence of such information, impact of imposition of anti-dumping on PUC on the cost of Atorvastatin tablet has not been determined.
- iii. As regards the submission of the domestic industry on opportunity to clarify the basis of allocation, the Authority notes that the changes sought by applicant time and again in their NIP claim were considered by the Authority on merit. The basis of allocation was also explained to the domestic industry during the verification of data.
- iv. Regarding the contention of the domestic industry on salary and wages, the Authority has taken note of the following data;

(Source : format H and Format C submitted by DI)

Parameters given/claimed by Applicant in respect of PUC					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(POI)
PUC Production	MT	***	***	***	***
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Salaries & wages Cost for PUC Claimed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Salaries & Wages Cost for PUC Claimed	Rs./Kg	***	***	***	***
PUC Productivity	Kg/employee	***	***	***	***
Salaries & Wages Cost for Company as a whole	Rs. Lacs	***	***	***	***
PUC Production	Index	100	273	1000	1045
No of Employees	Index	100	115	148	151
Salaries & wages Cost for PUC Claimed (Rs. Lacs)	Index	100	435	2283	7726
Salaries & wages Cost for PUC Claimed (Rs./Kg)	Index	100	157	225	731
PUC Productivity (Kg/employee)	Index	100	238	668	688
Salaries & Wages Cost for Company as a whole (Rs. Lacs)	Index	100	131	127	152

It was noted that:

- a. Para 4(vi) of Annexure III of Anti-Dumping Rules provides that *"The expenses to the extent identified to the product are to be directly allocated and common expenses or overheads classified under factory, administrative and selling overheads may be apportioned on reasonable and scientific basis such as machine hours, vessel occupancy hours, direct labour hours, production quantity, sales value, etc., as applied consistently by domestic producers and the reasonableness and justification of various expenses claimed for the period of investigation may be examined and scrutinised by comparing with the corresponding amounts in the immediate preceding year."*
- b. On such comparison with the corresponding amounts during the immediate preceding year as mentioned in the above table, it is seen that the productivity of the PUC has increased by 13 basis points, the salary cost of the company has increased by 25 basis points, while the salary cost claimed for the PUC in Rs. Lacs and in Rs./Kg has increased by 5543 basis points and 506 basis points respectively.

- c. The domestic industry was not able to provide the reasonable justification with the supporting documents about the increase in salary cost in the POI (2020-21), compared to previous year/ IIP (2019-20), when there was no significant change in number of employees and change in production quantity of PUC.
- d. Moreover, the allocation methodology adopted by Authority in respect of salary and wages allocation i.e Production Ratio is in consonance with the allocation methodology followed by the applicant during previous years/Injury Investigation periods.
- v. Regarding the contention of the domestic industry on job work, the Authority notes that neither Domestic Industry's application nor the company's Annual Financial Statement mentions about any such job work carried out by them during the POI. Secondly, the domestic industry could not produce any MoU or any supporting documents in this regard. Therefore, the Authority has considered the production and sales as per the available the domestic industry's claim and record.
- vi. Regarding the contention of the domestic industry on reasonable return on capital employed while calculating the NIP, the Authority notes that Annexure III (viii) of Anti-Dumping Rules, 1995 provides that "*A reasonable return (pre-tax) on average capital employed for the product may be allowed for recovery of interest, corporate tax and profit*". As per DGTR's practice 22% return on average capital employed has been provided. The 22% return so provided is inclusive of interest cost, tax and profit.
- vii. The Authority has taken cognizance of the higher finance cost of the domestic industry. The same has been considered appropriately principles laid down in Annexure III of Anti-Dumping Rules. In this regard, it is further noted that the annual report of domestic industry mentions that deterioration of net worth is due to higher provisioning of interest. Therefore, injury to that extent cannot be attributed to dumped imports.
- viii. The Authority, therefore notes that there is no merit in the claim/contentions made by the domestic industry on the disclosure statement in respect of the NIP calculated by the Authority.
- ix. The constructed normal value is determined on the basis of the price actually paid or payable in India on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

91. Various submission of the interested parties and petitioner on the aspect of Indian industry's interests and other issues are considered and examined as follows:

K.1. Submissions made by other interested parties

- i. Imposing anti-dumping duty on imports of the PUC would be against public interest.
- ii. The price of the finished Atorvastatin Formulation is controlled by the Drug (Prices Control) Order, 2013 and the respondents will have to bear the burden of Anti- Dumping Duty, if any, imposed.
- iii. The price of Atorvastatin formulation, being an essential commodity is controlled by the DPCO. The following table shows the prices of Atorvastatin Formulation as per the DPCO:

Particulars	Ceiling price per tablet w.e.f. 01.04.2020 in terms of Order dated 25.03.2020	Ceiling price per tablet w.e.f. 01.04.2021 in terms of Order dated 25.03.2021
Atorvastatin- 10mg	5.47	5.50
Atorvastatin- 20mg	13.25	13.32
Atorvastatin- 40mg	19.24	19.34
Source: Orders dated 25.03.2020 and 25.03.2021 fixing the ceiling prices in terms of the DPCO		

- iv. The price increase as per the DPCO is also very minimal and is based on the Wholesale Price Index of 0.53568% from 2020 to 2021. Therefore, such increase will not cover the increase in costs due to the Anti-Dumping Duty.
- v. When the price of formulation is controlled by DPCO, the respondents will not be in a position to increase the price of the API. At the same time, the respondents are the users of the PUC and therefore, have to bear the increase in price of the PUC through Anti- Dumping Duty, if any imposed.
- vi. Atorvastatin Tablet of 5 mg strength is not an essential commodity and not controlled by the DPCO. However, the market share of the same in the overall market of Atorvastatin formulation is very less. Significant market is for tablets of 10mg, 20mg and 40mg, prices of which are controlled under DPCO.
- vii. The cost of the PUC constitutes about [30% - 40%] of the cost of Atorvastatin API. Further, cost of the PUC constitutes about [5% - 15%] of the cost of Atorvastatin formulation. Dr. Reddy's manufactures and sells Atorvastatin API Amoli Organics manufactures and sells Atorvastatin API. Thus, an Anti-Dumping Duty of 20-30% will have a significant impact on the profitability of the respondents.
- viii. Imposition of the anti-dumping duty will not be in public interest and will adversely affect the respondents' business.
- ix. The PUC is used for manufacture of Atorvastatin tablet which is a life-saving drug used to lower the cholesterol levels. The onset of the Covid-19 pandemic has led to various side effects, one of which is the high cholesterol levels amongst many who have recovered from it. Atorvastatin is one of the drugs prescribed to overcome the high cholesterol levels arising due to the Covid-19 Pandemic.

K.2. Submissions made by the domestic industry

- i. The existence of the domestic industry producing the subject goods shall be in the larger public interest and the oppositions raised against the ADD citing public interest are all only motivated statements to take the benefit of dumping being practiced by the exporters.
- ii. ATS-8 is a pharmaceutical intermediate which goes into the production of Atorvastatin API which further goes into the manufacturing of Atorvastatin formulations/drugs to reduce cholesterol in human beings. Petitioner is the sole producer of the subject goods in India and the existence of the petitioner shall be essential to ensure the domestic supply of this important pharma intermediate. Else, the country as such will be dependent on the imports from China PR for ATS-8 which cannot be a situation in larger public interest in any manner.
- iii. In the absence of production and supplies by the petitioner, the users in India shall be dependent only on the imports from China PR and it will have adverse effects in terms of both price and volumes.
- iv. The users may be able to benefit in the short term based on the dumped imports but the price can increase irrationally when there is no domestic supply of the product in India and in a situation of imports enjoying a monopolistic situation in the Indian market.
- v. The opposing parties have not quantified the effect of any ADD on the end formulation. No actual cost and price details are provided to substantiate the claims. Any ADD on the subject goods will have very negligible price effects on the Atorvastatin formulation and the Atorvastatin API producers and formulation producers shall be well placed to pass on such minimal price increases on account of any ADD to be imposed on ATS-8.
- vi. As per the estimate of the petitioner, ATS-8 may account for a meager 1.5% to 2% cost of Atorvastatin Drug and any ADD will have only very minuscule effect on the end drug as the cost of intermediate in such drug as such is very small. The general public will not be impacted on account of ADD in any significant manner.
- vii. It has been a contention that imposition of ADD will have a huge impact on the profitability of the Atorvastatin API manufactures as the price in the industry for Atorvastatin formulation in India is regulated by Drug Price Control Order, 2013. The contention is totally unsubstantiated and no real data is submitted to show the impact on formulation as alleged.

- viii. The regulations under DPCO are dynamic pricing mechanism and the prices fixed under the DPCO by NPPA take into consideration the input cost for the product and also reasonable profit and the prices are amenable to changes based on any material changes in the input cost etc. ADD on the product will not have any serious impact on the fair input cost considered for price regulation under DPCO.
- ix. The formulators will not suffer in any manner as alleged and the contention is only an attempt to misguide the Authority. It is also a settled principle that ADD will have some impact on the cost at the end of the users but the ADD is always determined as a measure to remove the injurious effects of dumping and not beyond that. ADD will only stop the price distortion and is not any measure which will create any price increase per se.
- x. Price regulation of an end formulation wherein the subject good is an intermediate is not any barrier under the AD Rule in seeking protection against dumped imports of the intermediate by the producer of the intermediate. The issue had been addressed in the past by the Authority in matters like ADD Investigation concerning Gliclazide originating in or exported from China PR and a similar view is essential in the present matter also.
- xi. ADD to the extent to ensure fair price for the product cannot be construed as any measure against the public interest and ADD in the present matter will only ensure a fair balance between interest of the importers/users and the producer of ATS-8 in India.

K.3. Examination by the Authority

- 92. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by the dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 93. The Authority considers whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to examine the same, the Authority has weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is proposed to be based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
- 94. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The submissions adduced by the two users/importers participating in the present investigation have been considered to the extent supported by evidences.
- 95. With regard to the contention that price of Atorvastatin Formulation, being an essential commodity, is controlled by the DPCO and any ADD will have major impacts on downstream users and end users due to such price control, the Authority notes that the subject product is a pharmaceutical intermediate which goes into the production of Atorvastatin API which further goes into the manufacturing of Atorvastatin Formulation/drug. The price as fixed by DPCO is applicable on the final drug.
- 96. Further, the Authority notes that while the price of the final drug is fixed by DPCO, there could be an increase in the cost of production in the two downstream stages of API production and later the drug production. While one of the main API producers has given inputs on quantification of cost incurred for the API, the further cost increase at the drug stage has not been provided by any interested party. The Authority has considered all the submissions on the aforesaid issues made in response to this final finding.

L. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

97. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping, and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration has been exported from the subject country at a price below the normal value, thus resulting in dumping.
 - b. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry shows that the volume of imports from the subject countries have increased in absolute terms and also in relation to consumption in India.
 - c. While the demand has increased from 100 basis points to 137 basis points, the sale of the domestic industry increased from 100 basis points in the base year to 1027 basis points in the POI. However, the domestic sales account for only 20% of total demand of the subject goods in India. Further, it is noted that the domestic industry has been able to increase its domestic sales by keeping the net sales realization much below the landed price.
 - d. The capacity utilization, production and sales of the domestic industry increased during the injury investigation period including the POI. However, the capacity utilization of the domestic industry has been very low in the entire injury period.
 - e. The employment, wages and productivity increased during the injury investigation period including the POI.
 - f. The fall in the profitability of the domestic industry between base year and the POI has been very substantial.
 - g. The domestic industry is stuck below the landed price throughout the injury investigation period including the POI and has not been able to increase the prices. In this regard, the domestic industry has stated that the dumped imports prevented price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.
 - h. There is causal link between dumping of the product under consideration from the subject country and injury to the domestic industry
 - i. Further, the Authority notes that while the price of the final drug is fixed by DPCO, there could be an increase in the cost of production in the two downstream stages of API production and later the drug production. While one of the main API producers has given inputs on quantification of cost incurred for the API, the further cost increase at the drug stage has not been provided by any interested party. The Authority has considered all submissions on the aforesaid issues made in response to this final finding. Since the duty recommended is based on injury margin as per the lesser duty rule, the duty recommended is fairly reasonable and it is not likely to cause any adverse impact on the downstream industry.
 - j. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
 - k. In terms of provisions contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of the goods described in col.3 of the duty table below originating in or exported from the subject country for a period of two years from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government. The anti-dumping duty is

recommended as the difference between the landed value of the goods as described in Col.3 of the duty table below and the amount indicated in Col.7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col.7. If the landed value is more than the value indicated in Col 7, the anti-dumping duty will not be applicable. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2520	(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd.	119.21	KG	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.	119.21	KG	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co., Ltd.	Nil	-	-
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Yutian Pharmaceutical Co., Ltd.	119.21	KG	USD
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than producer at S.no. 1 to 4	119.21	KG	USD
6	-do-	-do-	Any country other than China PR	Any	Any	119.21	KG	USD

M. Further Procedure

98. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority